A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 231, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

क्या विस चुनावों के बाद देश में आर्थिक दिक्कतों का दौर शुरू होगा?

अरविंद मोहन

डीजल, पेट्रोल और गैस की क़ीमतें क्या विधानसभा चुनावों की वजह से रुकी हुई हैं? 29 अप्रैल को जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी तो क्या महंगाई की मार के लिए तैयार रहना होगा? आर्थिक हालत कैसी है? जी हां, 29 अप्रैल तक भारत सरकार और उसके कर्ता-धर्ता बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। होने को तो पाँच राज्यों के चुनाव अभी अपनी प्रक्रिया के बीच ही हैं और 29 अप्रैल के पहले तमिलनाडु का मतदान भी पूरा हो जाएगा लेकिन बंगाल चुनाव का दूसरा और अंतिम फेज 29 अप्रैल को ही पूरा होगा और उसके बाद ही प्रधानमंत्री समेत सरकार के सभी प्रमुख लोगों का ध्यान उधर से हटेगा। सबके रिजल्ट 4 मई को आने हैं। लेकिन पाँच राज्यों की विधान सभाओं के परिणाम और देश की राजनीति पर उसका प्रभाव सामने आए इससे पहले ही 29 अप्रैल की रात से परिणाम आने की भविष्यवाणी करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला नंबर तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की क़ीमतों का होना चाहिए। और खैरियत यही है कि ईरान अमेरिका, इसराइल युद्ध की आंच मद्धिम पड़ी है और संभव लगता है कि 29 अप्रैल तक कोई समझौता ही हो जाए। माहौल अभी भी बदला है और पेट्रोलियम के दाम समेत शेयर बाजार और सर्राफा बाजार की तेजी कुछ मद्धिम पड़ी भी है। लेकिन इससे हम आप नई मूल्य वृद्धि से बच नहीं सकते।

और तय मानिए कि यह बदलाव सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों तक सीमित नहीं रहेगा। कई अन्य चीजों और सेवाओं के दाम भी सरकार बढ़ा सकती है। निजी क्षेत्र तो उसका इंतजार भी नहीं करता, वह अभी ही अपने उत्पादों और सेवाओं को महंगा करने लगा है। और जब सरकार के फैसलों से उसके ऊपर बोझ बढ़ेगा तो वह एक के बदले तीन पैसे की वसूली अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से शुरू कर देगा। सिर्फ सेवा देने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का दौर शुरू हो गया है और दस बारह साल से रुका पड़ा यह काम आंदोलनों के सहारे चला है और बढ़ता गया है।

पर मजदूरों में बेचैनी कीमतों में सामान्य वृद्धि और गैस की किल्लत और कालाबाजारी से ज्यादा बढ़ी। काफी सारे प्रवासी मजदूर तो इस चक्कर में अपने देश लौट गए। और उनके ही नहीं, आम आदमी के जीवन में ईंधन के महत्व को समझकर सरकार के स्तर पर सक्रियता हुई है। पेट्रोल और गैस के दाम न बढ़ाना भी उसी तरह की सक्रियता है। और इसके पीछे आम लोगों को राहत देना कितना बड़ा कारण है और पाँच राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव कितना बड़ा कारण है, यह समझना मुश्किल नहीं है। मोदीजी की राजनीति के लिहाज से चुनाव का मतलब सबसे ऊपर है। और इसी आधार पर चुनाव बीतते ही क़ीमतों में बढ़ोत्तरी की बात कही जा रही है।

यह संकेत भले मोदी जी की राजनीति को जानने वाले समझ जाएं, पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जो सूचनाएं आने लगी हैं वे बताती हैं कि चुनावी शोर चीजों को नज़रों से ओझल कर दे लेकिन आर्थिक सच्चाई पर परदा नहीं डाला जा सकता। सबसे पहले तो यही गणना बिगड़ गई है कि भारत दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह छठे नंबर पर खिसक गया है। अभी तक प्रधानमंत्री तीसरी अर्थव्यवस्था बनने बनाने की बात खूब करते थे, अब उनकी तरफ से कोई बयान इस बारे में नहीं आया है।

विकास दर दो फीसदी कम हो जाने का अनुमान लगभग सारे प्रमुख अर्थशास्त्री कर रहे हैं। फिर यह सूचना भी आने लगी है कि बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है और यह खाड़ी युद्ध का असर है।

यह सूचना भी आई है कि खाड़ी के देशों में भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में आई गिरावट से उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां परेशान हैं। खाड़ी देशों में एक करोड़ के आसपास हिन्दुस्तानी कामगार रहते हैं और जाहिर तौर पर अच्छी कमाई वाले ये लोग अपनी पसंद की भारतीय चीजें भी बड़े पैमाने पर खरीदते हैं। देसी मांग भी गिरी है। और कुछ चीजों की मांग तो ऐसे गिरी है कि सारा बाजार भौंचक्का है। इस अक्षय तृतीया को सोने की खरीद का रिकॉर्ड ऐसा ही है जबकि सोना और चांदी दोनों के भाव इधर काफी कम हुए थे।

और मामला सिर्फ़ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटने का नहीं है। उसकी कमी महंगाई के चलते भी होगी। और संयोग से खाड़ी युद्ध छिड़ने के पहले हमने उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांक में जो बदलाव किए वे अब नित नए रिकॉर्ड की सूचना दे रहे हैं। पर इससे ज्यादा चिंता कोर सेक्टर में उत्पादन के गिरावट की है और खासतौर से रासायनिक खादों के उत्पादन और खपत में गिरावट का। यह गिरावट नए रिकॉर्ड बना रही है पर उससे भी ज्यादा भविष्य के लिए चिंता पैदा कर रही है। करोना वाली मंदी में भी कृषि ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक बनी थी। लगता है इस बार वह भी साथ छोड़ने जा रही है। और यह लेखक जिस नोएडा-गाजियाबाद के इलाके में बैठकर यह लेख लिख रहा है, वहां की और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी औद्योगिक गतिविधियां गैस की तंगी से परेशान है। काफी बंद पड़ी हैं। ऐसा अन्य औद्योगिक इलाकों की रिपोर्ट भी है। और इससे भी बढ़कर हुआ है कि इनके निर्यात का ऑर्डर आना बंद हो गया है। जाहिर है यह संकट को लंबा खिंचेगा।

यह सब गिनवाने का मतलब कोई आतंक पैदा करना नहीं है। और ना ही यह बताना ही है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। निश्चित रूप से युद्ध शुरू होने के पहले हमारी अर्थव्यवस्था के ज्यादातर संकेतक हरा रंग ही दिखा रहे थे। और हम दुनिया में सबसे तेज़ विकास दर का दावा भी कर रहे थे। लेकिन उस युद्ध ने जिसका हमसे कोई सीधा वास्ता नहीं है और न ही हमने खुद को उलझने दिया, उसका प्रभाव इतना ज्यादा आ जाए, यह हमारे प्रबंधन की गड़बड़ी है। रुपए का टूटना हो या सोने चांदी में तेजी का, विदेश व्यापार में परेशानी हो या विकास दर की, आप सिर्फ और सिर्फ सस्ते श्रम के मत्थे अपना तेज विकास चाहते हैं और दुनिया को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो यह भ्रम है। इसे जल्दी छोड़िए। लेकिन इससे भी बड़ा भ्रम चुनावी जीत का है। सारा कुछ छोड़कर दिन रात और हर कर्म करके चुनाव जीतने पर लगे रहने का जनादेश आपको क्या किसी को नहीं होता। इसलिए 29 अप्रैल और चार मई के इंतजार को दूसरा मतलब दीजिए। अभी से भी अपने असली काम में जुटिये। इसकी बहुत जरूरत है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

चुनावी रैली में पीएम मोदी बोले-

झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्च विपक्षियों को लग रही

कहा- 4 मई को परिवर्तन होगा, हावड़ा में किया रोड शो

कोलकाता (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल के मथुरापुर और कृष्णानगर में चुनावी रैली की । उन्होंने कहा- जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। मोदी ने कहा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा को पूजती है, लेकिन टीएमसी ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की। टीएमसी की सरकार में गुंडों और बलात्कारियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। बंगाल की बेटियां ये अत्याचार कभी नहीं भूल सकतीं। चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने पर उन्होंने कहा- झालमुड़ी मैंने खाई है पर मिर्च विपक्ष को लग रही है। अब का मतदान सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

भवानीपुर में ममता ने की पदयात्रा, कहा एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में रोड शो कर रही हैं। ममता वहीं से विधायक हैं। ममता ने कहा एसआईआर के विरोध में जमकर मतदान हुआ है ।29 अप्रैल को दूसरे चरण में वहां वोटिंग होनी है।

घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालेंगे: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली के बालागढ़ में कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठ पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और जो घुसपैठिए यहां रह रहे हैं, उन्हें चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और बंगाल के युवाओं के हक की नौकरियां व गरीबों का राशन छीन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना।29 तारीख को को आरमबाग वालों को परेशान किया तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे।

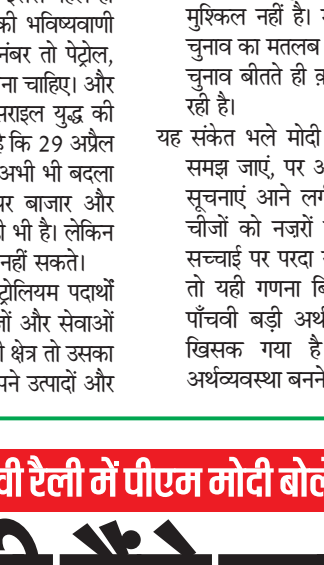

बंगाल के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु सरकार को दौड़ाकर पीटा

कोलकाता/चेन्नई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट सुवेंदु सरकार पर हमला हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि सुवेंदु हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके

बावजूद भीड़ सुवेंदु को पीटती है।

इधर, बर्नपुर के रहमतनगर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। अग्निमित्रा ने हीरापुर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में कई अन्य जगहों पर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई हैं।

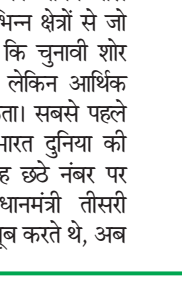

बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना, पहले फेज में 90 प्रतिशत मतदान

- **तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा 82 प्रतिशत वोट पड़े**

कोलकाता/चेन्नई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बंपर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 89.93 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 82.24 प्रतिशत वोटिंग हुई।

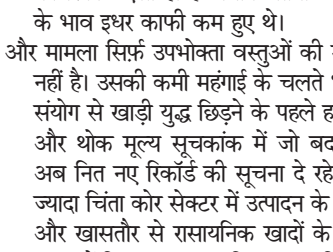

दोनों राज्यों के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े शाम 5 बजे तक हैं। इनमें बदलाव हो सकता है।

इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को

रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.91 प्रतिशत, पुडुचेरी में 90 प्रतिशत और केरलम में 1987 के बाद सबसे ज्यादा 78.27 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

subhahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

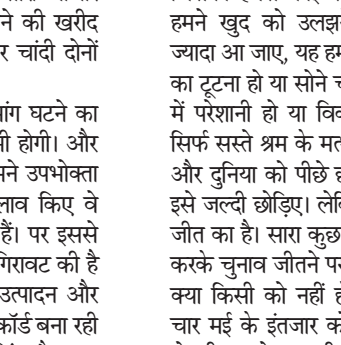

कई लोग भूखे खड़े हैं कतार में
रोटी के इंतज़ार में
कई लोग प्यासे खड़े हैं कतार में
पानी के इंतज़ार में
कई लोग अधनंगे खड़े हैं कतार में
पूरा तन ढंकने के इंतज़ार में
कई लोग बेघर खड़े हैं कतार में
घर के इंतज़ार में
कई लोग खड़े हैं कतार में
दुकान खुलने के इंतज़ार में
कई लोग खड़े रहते हैं कतार में
कुछ और जी लेने के इंतज़ार में
लोग बार- बार खड़े होते हैं कतार में
सरकार चुनने के इंतजार में
लोग चुनते रहते हैं सरकार खड़े होकर कतार में
रोटी-कपड़ा और मकान के इंतज़ार में।

- ध्रुव शुक्ल

यूपी बोर्ड : 10वीं में छात्राओं ने लहराया परचम

- 10वीं में सीतापुर की कशिश, बाराबंकी की अंशिका टॉपर, मेरिट में 123 बच्चे

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने टॉप किया है। दोनों को 97.83 प्रतिशत अंक मिले हैं। 97.50 प्रतिशत अंकों के साथ बाराबंकी की अदिति दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर 97.33 प्रतिशत अंकों के साथ सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा रहीं। इस तरह टॉप-3 में कुल 6 बच्चों ने अपनी जगह बनाई। खास बात यह है कि इनमें 5 लड़कियां हैं। टॉप-10 की बात करें तो 115 बच्चों ने जगह बनाई है।

किसानों से गेहूं का एक-एक दाना खरीदेगी राज्य सरकार

माताओं-बहनों को सर्वोपरि रखने की है हमारी संस्कृति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल /सागर (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी संस्कृति माताओं-बहनों का सर्वोपरि रखने की रही है। बहनों को विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण दिलवाने के लिए हमारी सरकार लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबको साथ लेकर चलने के लिए सभी से अपील की थी, लेकिन कुछ राजनैतिक दलों को बहनों को उनका अधिकार देने में जरा भी दया नहीं आई। पहले भी बहनों के भरण पोषण के भत्ते से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी इन लोगों ने ही ठुकरा दिया था। राज्य सरकार माताओं-बहनों का सम्मान करते हुए लाड़ली बहना योजना के माध्यम से बहनों को हर महीने 1500 रुपए की सौगात दे रही है। प्रदेश के 17 जिलों में महिला कलेक्टर हैं। प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में महिला अधिकारी एसपी हैं और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। सागर जिले में सांसद, महापौर भी महिलाएं हैं। प्रदेश भर में प्रमुख पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन कई राजनैतिक दलों को नहीं सुहाता है। माताएं-बहनें सब कुछ भूल सकती हैं, पर अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती हैं, बहनों से यही अपील है कि मौका मिलने पर हिसाब जरूर चुकता करना है। हमारा पूर्ण संकल्प है कि आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में इन बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का अस्थाई कनेक्शन दिया जा रहा है। किसान भाइयों की मेहनत से प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन भी बढ़ा है। अब पॉली बैग्स का विकल्प निकाला गया है। राज्य सरकार ने गेहूं का एक-एक दाना खरीदने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, नरयावली, सागर में विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नरयावली में सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण एवं अन्य विकास कार्यों के भूमि-पूजन एवं लोकार्पण समारोह में कन्या पूजन किया।

सच्चा वादा, पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम हमारी सरकार का नारा है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर उपज का उचित दाम दिलवाया था। सच्चा वादा, पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम हमारी सरकार का नारा है। जो कहा है, उसे पूरा करके दिखाया है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में नए सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, बांध, सड़कें और उद्योग सहित अन्य विकास कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर किसानों से भूमि अधिग्रहित की जाती है। जमीन ही किसानों का आसरा होती है। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को भूमि अधिग्रहण करने पर कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा।

गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम

राशन दुकानों से मिलेगा खाना पकाने का कोयला

पटना (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध आपके रसोईघर का तेल निकालने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर की डगमगाई आपूर्ति व्यवस्था ने सरकार को कोयले पर कंधा टिकाने को मजबूर कर दिया है। अब खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर के बजाए कोयला खरीदना होगा। वह भी राशन कार्ड पर। प्रत्येक लाभुक परिवारों को प्रति माह एक क्विंटल कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार सरकार ने राशन दुकानों तक कोयले की सप्लाई की बड़ी तैयारी कर लेने का फरमान जारी कर दिया है। यह व्यवस्था सिर्फ राशन कार्डधारियों के लिए है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से ऊर्जा की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। राज्य में गैस सिलिंडर की सप्लाई बाधित होने से लोगों को समस्या हो रही है। गैस सिलेंडर की कमी से निपटने के मकसद से खाना पकाने के लिए कोयले की सप्लाई होनी है।

ऐसे में आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वालों को कुकिंग के लिए कोयला दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कोल हेड से घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन तैयार कर लिया है, जिससे लोगों को खाना पकाने में दिक्कत नहीं होगी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

2006 मालेगांव ब्लास्ट केस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को किया बरी, जांच एजेंसियों पर उठाए गंभीर सवाल

मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 मालेगांव बम धमाका मामले में अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने मामले की जांच पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केस अब डेड एंड यानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल नजर आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों की परस्पर विरोधी कहानियों ने पूरे मामले को उलझा दिया है।

कोर्ट ने आरोपों को रद्द करते समय क्या कहा?

हाईकोर्ट ने राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवरिया और लोकेश शर्मा को राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने सितंबर 2025 में विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत ने आरोप तय करते समय उपलब्ध साक्ष्यों और विरोधाभासों पर सही ढंग से विचार नहीं किया।

ईरान बोला- ट्रम्प का सीजफायर एकतरफा

- अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तभी बात करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- कल तक अच्छी खबर आ सकती है

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीजफायर से इनकार किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालीबाफ ने कहा कि मौजूदा समय में सीजफायर तभी

संभव है, जब नाकाबंदी हटाई जाए। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो गया था। ट्रम्प ने इसके खत्म होने से पहले ही इसे एकतरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया था। वहीं, ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प ने एक संदेश में यह बात कही।

पेट्रोल-डीजल 28 रू. महंगा होने की खबरें गलत

- सरकार बोली- दाम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25-28 रू. प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबरों को सरकार ने गलत बताया है। आज यानी 23 अप्रैल को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये खबरें भ्रामक हैं और डर फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं।

भारत में पिछले 4 साल से नहीं बढ़े दाम- सरकारी बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा देश है, जहां पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

आस्था और उत्साह के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट

मंदिर के कपाट खुलते ही गूंजे जय बदरीविशाल के जयकारे

देहरादून/ बदरीनाथ (एजेंसी)। बदरीनाथ धाम में गुरुवार सुबह मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भक्ति और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बैसाख मास के शुभ अवसर पर पुनर्वसु नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग में ठीक सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोले गए। इस दौरान जय बदरीविशाल के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पावन अवसर पर मौजूद थे। कपाट खुलने से पहले निर्धारित परंपराओं का पालन किया गया। तड़के चार बजे भगवान कुबेर जी का दक्षिण द्वार से प्रवेश हुआ, जिसके बाद मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियां शुरू हुईं।

रावल, धर्माधिकारी और वेदपाठियों ने उद्धव जी के साथ मंदिर में प्रवेश कर विधिवत द्वार पूजन संपन्न कराया। इसके बाद तय समय पर कपाट खोल दिए गए और पूर्वाह्न 11 बजे से गर्भगृह में पूजा-अर्चना आरंभ हुई।

बदरीनथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया था। मंदिर परिसर और आसपास के मठ-मंदिरों को लगभग 25 कुंतल ऑर्किड और गेंदे के फूलों व फलों से सजाया गया था, जिससे धाम और पूरा क्षेत्र दिव्य दिखाई दिया। कपाट खुलने से एक दिन पूर्व ही उद्धव, तेल कलश और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बदरीनाथ पहुंच चुकी थी। वहीं, कुबेर की डोली बामणी गांव में रात्रि प्रवास के बाद धाम पहुंची। कपाट उद्घाटन के इस आयोजन में आस्था, परंपरा और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। इससे पहले सीएम धामी ने बदरीनाथ धाम पहुंचकर यहां हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की।

बिहार में सम्राट सरकार का फैसला

11 शहरों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक!

सैटेलाइट सिटी प्लान से बदलेगा बिहार का नक्शा

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें सबसे अहम फैसला जमीन खरीद-फरोख्त पर रोक से जुड़ा है। राज्य के 11 प्रमुख शहरों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

सरकार का मकसद अनियंत्रित विकास पर रोक लगाना है। साथ ही योजनाबद्ध शहरी विस्तार को बढ़ावा देना भी है।

इन शहरों में लागू हुआ प्रतिबंध- पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा भी सूची में हैं।

सैटेलाइट सिटी प्लान से बदलेगा खेल

सरकार इन शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगी। इससे भीड़भाड़ वाले शहरों का दबाव कम किया जाएगा। नए शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जाएंगी। यह कदम शहरीकरण को व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम है। रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार के विकास मॉडल में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

मास्टर प्लान बनने तक पूरी तरह रोक

नगर विकास विभाग के अनुसार मास्टर प्लान बनने तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह का निर्माण कार्य भी नहीं होगा। लैंड यूज, कोर एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका तैयार किया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित किया जाएगा।सरकार अव्यवस्थित बसावट को रोकना चाहती है। मास्टर प्लान के बाद ही आगे की अनुमति दी जाएगी।

अलग-अलग शहरों के लिए अलग समय सीमा

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा में रोक 30 जून 2027 तक रहेगी। वहीं पटना समेत अन्य शहरों में यह 31 मार्च 2027 तक लागू है। समय सीमा तय कर सरकार ने स्पष्ट रोडमैप दिया है।

बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचे

- 'धर्मराज युधिष्ठिर' और 'दुर्योधन', हनुमान कथा के मंच पर सब हो गए चकित

छतरपुर (नप्र)। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों में प्रयागराज में हनुमान कथा कह रहे हैं। हनुमान कथा के मंच लगातार खास लोगों का आना जारी है। बागेश्वर बाबा के सोशल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन ने एक साथ बाबा से भेंट की है।

दरअसल, महाभारत सीरियल में धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन के किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेत बाबा बागेश्वर के मंच आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। महाभारत सीरियल में अभिनेता गजेंद्र चौहान ने युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। वहीं, पुनीत इस्सर ने दुर्योधन की भूमिका निभाया था। दोनों ने हनुमान कथा के मंच पर बाबा के साथ बातचीत की है।

श्रद्धालु रह गए चकित- वहीं, हनुमान कथा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन को देखकर वहां श्रद्धालु चकित रह गए हैं। 1990 के दशक में दोनों अभिनेता टीवी के स्टार थे। हर घर में उस समय महाभारत देखी जाती थी। ऐसे में लोग दोनों को देखकर हैरान थे। काफी देर तक कथा के मंच पर दोनों बैठे रहे हैं।

बाबा के साथ हुई हंसी ठिठोली- इसके साथ ही मंच पर जब गजेंद्र चौहान और पुनीत इस्सर बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो मंच पर हंसी ठिठोली भी हुई है। गजेंद्र चौहान जब बाबा को कुछ कहते हैं तो तीनों मंच पर जोरदार ठहाका लगाते हैं। बागेश्वर बाबा ने गजेंद्र चौहान को साधु जी सीताराम नाम की किताब भी भेंट की है। दोनों अभिनेताओं ने मंच से श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया है। गौरतलब है कि बागेश्वर बाबा प्रयागराज में हनुमान कथा कर रहे हैं। हनुमंत कथा के दौरान बड़ी संख्या में अलग-अलग क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ है। ऐसे में पूरा इलाका भक्तिमय है।

गंगा सप्तमी पर लिया जल संरक्षण का संकल्प

खटलापुरा घाट और छोटे तालाब की सफाई की, स्वच्छता कर्मियों का किया सम्मान

भोपाल (नप्र)। गंगा सप्तमी के अवसर पर भोपाल में गुरुवार को जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में निर्मल गंगा जन अभियान (भागीरथी जलाभिषेक) के तहत खटलापुरा घाट और छोटा तालाब परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सुबह 8 से 9:30 बजे तक चले इस आयोजन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए जिला, तहसील, नवचेतना केंद्र, महिला मंडल, युवा मंडल और प्रज्ञा मंडल के परिजनों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा के कलश पूजन और वैदिक विधि-विधान से हुई, जिसके बाद घाट और तालाब क्षेत्र में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान जल शुद्धि और तट शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने न सिर्फ घाट परिसर की सफाई की, बल्कि लोगों को जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम का एक भावनात्मक पहलू भी सामने आया, जब गायत्री परिवार ने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान कर उनके योगदान को सराहा।

जिला जल एवं पर्यावरण अभियान सदस्य राम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देना है।

मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यों के शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति की बैठक मान.सभापति विजेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई। इस बैठक में सदस्य दिनेश राय मुनमुन एवं श्री नरेंद्र प्रजापति सहित मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अरविन्द शर्मा उपस्थित थे।

मिर्जापुर में हादसा- बोलेरो में 9 जिंदा जले, 11 की मौत

- बेटे का मुंडन कराकर लौट रहा था परिवार, कोई नहीं बचा, शवों को पहचानना मुश्किल

मिर्जापुर (एजेंसी)। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें बोलेरो सवार 9 लोग जिंदा जल गए। हादसा रात 9.30 बजे मिर्जापुर-रीवा नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गया। ट्रक ने आगे चल रही बोलेरो और स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियां आगे चल रहे एक ट्रॉले से जा टकरा गईं। रफ्तार तेज होने की वजह से टक्कर के बाद बोलेरो उछलकर अलग हो गई। तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। जबकि, स्विफ्ट कार ट्रक और ट्राले के बीच में फंस गई। आग इतनी भीषण थी कि बोलेरो सवार 9 लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

जिसका मुंडन कराने गए थे, उस बच्चे की भी मौत

मिर्जापुर डीएम ने बताया- जिगना थाने नरैना निवासी अरुण सिंह का परिवार 8 साल के बेटे शिवा का मुंडन कराने मैहर गया था। हादसे में शिवा और उसकी मां वंदना की भी मौत हो गई है। इसके अलावा उनके रिश्तेदार पति-पत्नी और उनकी बेटी की भी मौत हो गई।

उत्तराखंड में गाड़ी खाई में गिरी, 8 की मौत

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के टिहरी में चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर नैल के पास वाहन खाई में गिर गया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने लोगों की मौत की पुष्टि की। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और राहत दल घटनास्थल पर पहुंचा। बचाव कार्य शुरू किया गया है। मरने वाले सभी लोग घनसाली क्षेत्र के चांजी, ठेला और चकरेडा गांव के रहने वाले थे। मृतक सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए थे।

सबरीमाला केस
जस्टिस नागरत्ना बोलीं

वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं चाहिए

- थरूर के आर्टिकल के जिक्र पर सीजेआई ने कहा- लेख पर्सनल ओपिनियन

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी दाउदी बोहरा समुदाय की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल की दलील के जवाब में की थी। कौल ने कहा था कि ज्ञान और समझ, चाहे वह किसी भी सोर्स से मिली हो, उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। कौल एक अखबार में कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर के लिखे लेख का हवाला दे रहे थे।

सबरीमाला मामले पर 7 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई

सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई है। पहले 3 दिन, 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

- ओडिशा में गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना रोकी गई

देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीटवेव जारी

- राजस्थान-यूपी में सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा; मप्र में भी पारा हाई, देश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ (एजेंसी)। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीटवेव जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। महाराष्ट्र का वर्धा और ओडिशा का झारसुगुड़ा बुधवार को 44.6 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं देश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हीटवेव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यानी फील्ड स्टाफ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान सड़कों पर नहीं भटकेंगे। राजस्थान और यूपी में ठंडक के लिए सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है। बीकानेर, ग्वालियर के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं।

लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत

भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने चार अहम आयोगों के अध्यक्षों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिससे साफ है कि सरकार अब नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेजी देने के मूड में है। जारी लिस्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर कैलाश जाटव का नाम तय किया गया है। महिला आयोग की कमान रेखा यादव को सौंपी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में रामलाल रौतेल को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा को बनाया गया है। इन नियुक्तियों को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से लंबित पड़ी इन नियुक्तियों को लेकर संगठन और सरकार के बीच लगातार मंथन चल रहा था, जिसके बाद अब इन नामों पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि आयोगों में नियुक्तियों के साथ ही अब निगम-मंडलों और अन्य बोर्ड्स में भी जल्द ही नियुक्तियों का सिलसिला तेज होगा। इससे पार्टी संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के साथ-साथ राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इन नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अब नजर आगे आने वाली निगम-मंडल सूची पर टिकी हुई है।

आकाशवाणी द्वारा तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

भोपाल। आकाशवाणी के 90वें प्रसारण वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा 23 अप्रैल को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन में भारतीय संस्कृति एवं धरोहर विषय पर आधारित तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी सशक्त अभिव्यक्ति, विचारशीलता एवं वक्तव्य कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम अधिकारी मनीष गजभिये ने विद्यार्थियों को आकाशवाणी के विविध कार्यक्रमों, उनके उद्देश्यों तथा समाज में उनकी भूमिका और महत्ता से अवगत कराया। इसके अंतर्गत 'एक दिन का आर जे' बनने की विशेष प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन के छात्र सिद्धांत शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें आकाशवाणी के लोकप्रिय युववाणी कार्यक्रम में एक दिन के लिए आरजे बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी विक्रम कुमार रंजन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की सराहना करते हुए कार्यक्रम प्रमुख चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ युवाओं को भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, तार्किक चिंतन एवं प्रभावी संवाद क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

करुणाधाम आश्रम में प्राचीन शैली पर आधारित भव्य शिवालय का होगा निर्माण

24 अप्रैल को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा भूमि-पूजन

भोपाल। धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत करुणाधाम आश्रम द्वारा प्राचीन भारतीय स्थापत्य शैलियों पर आधारित एक भव्य शिवालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका यह शिवालय भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं वास्तुकला की समृद्ध विरासत को दर्शाएगा।

इस भव्य निर्माण कार्य का भूमि-पूजन 24 अप्रैल को सुबह 8:30 से 10 बजे तक विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा। इस अवसर पर उज्जैन के प्रख्यात विद्वान डॉ. केदारनाथ शुक्ल तथा करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर गुरूदेव श्री सुदेश जी शांडिल्य महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। आश्रम प्रबंधन के अनुसार यह शिवालय न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी नई दिशा देगा। यह पहल धार्मिक चेतना के साथ प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि आश्रम परिसर में राम भक्त श्री हनुमान, माँ माता महालक्ष्मी और विघ्य विनाशक श्री गणेश जी महाराज पूर्व से ही विराजमान हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर बधाई दी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि चार धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। यह अवसर सनातन धर्म, आस्था एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सनातन अनुयायियों एवं तीर्थयात्रियों को दिव्य यात्रा के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं तथा बाबा बद्रीनाथ से सभी पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की है।

सीएम ने भगवान श्री चित्रगुप्त के प्राकट्योत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दीं- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्योत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान चित्रगुप्त की कृपा की कामना करते हुए सबके जीवन में मंगल और सुख-समृद्धि का वास बनाए रखने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की कृपा सब पर बनी रहे और सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है।

कॉमरेड होमी दाजी जन्म शताब्दी समारोह 26 अप्रैल को

भोपाल। अपने समय के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता और पूर्व सांसद कॉमरेड होमी एफ दाजी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में समारोह आगामी 26 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे स्थानीय हिन्दी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष में आयोजित किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ मार्क्सवादी चिंतक और कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड अजित कुमार जैन राजनीतिक चेतना और समकालीन परिदृश्य विषयक वक्तव्य देंगे।कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली करेंगे।

प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग का असर

भोपाल (नप्र)। उत्तर-मध्य रेलवे के प्रयागराज स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमोडलिंग कार्य का असर अब भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन 20 ट्रेनों के मार्ग में अस्थाई बदलाव करते हुए उन्हें प्रयागराज स्टेशन के बजाय प्रयागराज छिवकी स्टेशन के रास्ते चलाने का निर्णय लिया है। ब्लॉक अवधि के दौरान इस मार्ग की परिवर्तित ट्रेनों को प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थाई ठहराव भी दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। यह व्यवस्था ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान तिथि पर लागू रहेगी।

तिलक लगाना छोड़ो और पूजा बंद करो...

बाइबल थमाकर बोले, अब तुम ईसाई बन गए, खरगोन में प्रार्थना के बहाने धर्म बदलने का खेल

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र में कथित रूप से धर्मांतरण कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ग्रामीण की शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बमनाला निवासी बबलू पिता राजेश दागोडे (29 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई है कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वह सेल्दा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने राजू बडोले के घर पर काफी भीड़ देखी। जब वह वहां पहुंचा तो उसे घर के अंदर बुलाया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, अंदर मौजूद लोगों ने उसे ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए कहा और बताया कि ऐसा करने से वह हमेशा स्वस्थ रहेगा तथा उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आरोप है कि उसे अपने पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज छोड़ने के लिए भी कहा गया। उसे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा बंद करने, तिलक न लगाने और अपने धर्म का पालन नहीं करने के लिए कहा गया।

बाइबल देकर कहा, अब तुम ईसाई बन चुके हो!- शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कुछ देर बाद उसे बाइबल दी गई और कहा गया कि वह अब ईसाई बन चुका है। साथ ही उसे नए धर्म के फायदे बताए गए और यह भरोसा दिलाया गया कि धर्म बदलने के बाद उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

घटना के बाद शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भीकनगांव थाना क्षेत्र की बमनाला पुलिस चौकी ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों में राजू बडोले निवासी बमनाला, बबलू जमरे निवासी दसलगांव, पंकज बारिया निवासी झाबुआ और सेतु मेडा निवासी झाबुआ शामिल हैं। सभी के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजेंद्र अवास्या, चौकी प्रभारी बमनाला ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस साक्ष्य एकत्र करने और मामले की पुष्टि करने में जुटी हुई है

आरोपियों से 13 बाइबल लैपटॉप, साउंड बरामद

पुलिस ने उनके पास से तेरह बाइबल, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर और ईसाई साहित्य बरामद किया है। बमनाला चौकी प्रभारी राजेंद्र अवास्या ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

भोपाल में 93. 41 लाख का मुआवजा आदेश

जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला, इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा हर्जाना

भोपाल (नप्र)। भोपाल में सड़क दुर्घटना में फाइनेंस कंपनी में पदस्थ एक युवक की मृत्यु के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को 93 लाख 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश सड़क दुर्घटना करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और एमपी नगर भोपाल को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मृत्यु के दावा मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किए हैं। अधिवक्ता के अनुसार लालघाटी बैरागढ़ भोपाल निवासी 27 वर्षीय राहुल ठाकुर बजाज फाइनेंस कंपनी में पदस्थ थे। 27 अगस्त 2024 को रात्रि 9:30 बजे राहुल अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली आ रहे थे।

इसी दौरान एन.एच 45 ग्राम हरसिली पर पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए राहुल की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी थी।

मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से राहुल ठाकुर गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया था

उन्हें तत्काल ही शासकीय अस्पताल बरेली लेकर जाने पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित मोटरसाइकिल के चालक, स्वामी और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एमपी नगर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

जिला न्यायालय में मोटरसाइकिल के स्वामी,चालक और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से पेश किए गए जवाब में सड़क दुर्घटना के लिए राहुल ठाकुर को ही जवाबदार बताया जाकर उनके परिजनों की ओर से पेश किए गए मृत्यु के मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई थी।

भोपाल में 2 शराब दुकानों का विरोध

शाहपुरा में स्कूल से 50 मीटर दूर ही ठेका, अरेरा कॉलोनी में मंदिर के पास

भोपाल (नप्र)। भोपाल में शराब दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर विरोध का दौर जारी है। गुरुवार दोपहर लोगों ने अरेरा कॉलोनी और शाहपुरा में प्रदर्शन किया। शाहपुरा में स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर ही ठेका है, जबकि अरेरा कॉलोनी में मंदिर के पास है। यहां बीजेपी पार्षद भी विरोध में मैदान में उतर गईं।

अरेरा कॉलोनी की शराब दुकान का पिछले एक साल से लोग विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत हो चुकी है। वहीं, आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने निरीक्षण भी किया था। बावजूद ठेका नहीं हटा तो गुरुवार को लोग फिर से प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए। हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की।

अरेरा कॉलोनी के रहने वाले कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने बताया, यहां जिस जगह पर शराब दुकान संचालित हो रही है, वह पूरी तरह से आवासीय उपयोग के लिए है, लेकिन वर्तमान में इसका कमर्शियल तरीके से उपयोग हो रहा है, जो पूरी तरह मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उक्त शराब दुकान को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता त्रिपाठी, क्षेत्रीय पार्षद शिखा गोहिल, सचिन दास बब्बा,रवि शर्मा, लवनीश भाटी, पूर्णेंदु शुक्ला आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की और सरकार को चेतावनी दी अगर इस अवैध दुकान को जल्द नहीं हटाया गया तो अरेरा कॉलोनी के निवासी दुकान पर ताला बंदी करेंगे।

40 मीटर दूर ही है आर्य समाज मंदिर

रहवासी त्रिपाठी ने बताया कि स्थानीय लोग एक साल से जिला प्रशासन, नगर निगम, आबकारी विभाग और मानव अधिकार आयोग तक शिकायतें दर्ज कर चुके हैं। बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया, यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में शराब दुकान के 40 मीटर की दूरी पर स्थित आर्य समाज मंदिर को मंदिर मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शराब दुकान के कारण क्षेत्र की शांति, सामाजिक वातावरण और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। प्रतिदिन वहां पर भीड़, वाहनों की आवाजाही, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और शोर-शराबे की स्थिति बनी रहती है। जिससे महिलाओं और बच्चों के लिए आवागमन तक कठिन हो गया है। आवासीय भूखंड पर शराब दुकान चलाना न केवल अवैध है, बल्कि यह भोपाल नगर निगम के मानचित्र और भूमि उपयोग नीति के भी पूरी तरह विपरीत है।

शाहपुरा में भी विरोध का दौर

शाहपुरा थाने के बाद गुलमोहर कॉलोनी इलाके में ही शराब की दुकान खोले जाने से स्थानीय रहवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। रहवासियों का आरोप है कि बच्चों के स्कूल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोली गई है, जो नियमों का उल्लंघन है। स्थानीय नागरिकों, स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों एवं छोटे-छोटे बच्चों ने इस शराब दुकान को बंद कर अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। गुरुवार को भगवा पार्टी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

यहां भी हो रहे प्रदर्शन

- ऋषिपुरम अवधपुरी इलाके में भी लोग पिछले 18 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
- कोलार रोड स्थित मंदाकिनी चौराहे पर ठेका शिफ्ट होने का विरोध हो रहा है। रोज शाम को यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है।
- सेमराकलां की शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर पिछले एक साल से लोग जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। वर्तमान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
- ईंटखेड़ी की शराब दुकान को लेकर भी प्रदर्शन हो चुका है।
- प्रोफेसर कॉलोनी में पॉलिटेक्निक चौराहे की दुकान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आंदोलन कर चुकी है।

बरखेड़ी हनुमान मंदिर से निकली भव्य शोभायात्रा

भक्ति में झूमे श्रद्धालु, तीन दिवसीय प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पातरा बरखेड़ी स्थित हनुमान मंदिर में तीन दिवसीय प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन पर गुरुवार को भव्य शोभायात्रा निकाली गई। आकर्षक झांकियों, गाजे-बाजे और धर्म ध्वजाओं के साथ निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। शोभायात्रा के दौरान भगवान का नगर भ्रमण कराया गया। श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों की थाप पर भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। रास्तेभर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। यात्रा अलग-अलग मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया।

मीडिया प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया कि प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, राम-जानकी सीता दरबार के साथ बाबा खाटू श्याम की प्रतिमाओं की विधि-विधान से स्थापना की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रतिमा स्थापना का सौभाग्य लक्ष्मी परिवार के पूर्व पार्षद संजय साहू, सुधा साहू, रौनक साहू, रोशनी साहू, उर्मिला साहू, सुरेश साहू, शिवा साहू, पुरुषोत्तम साहू, शिखा साहू, देवराज साहू, रियांस साहू, मीना साहू, हर्ष साहू, मेघा साहू, शेष साहू, अनन्या साहू, सुप्रिया साहू, शिवम साहू (अमेरिका), मंजीत साहू, रजनी साहू और अक्ष साहू परिवार को प्राप्त हुआ।

एमपी में चार गुना मुआवजे पर जयराम रमेश बोले

मनमोहन सरकार के कानून को अपना बताकर झूठी वाहवाही लूट रही मप्र सरकार

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे को 2 गुना से बढ़ाकर 4 गुना करने के फैसले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है।

एक ओर जहां राज्य सरकार इसे किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार पर 'क्रेडिट चोरी' और किसानों को 'गुमराह' करने का आरोप लगाया है।

यह मनमोहन सरकार के 2013 के कानून की बहाली मात्र

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरते हुए कहा कि यह कोई नया उपहार नहीं है, बल्कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा सितंबर 2013 में बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून का हिस्सा है।सच्चाई यह है कि 2013 के कानून में ही ग्रामीण भूमि स्वामियों को 4 गुना मुआवजे का प्रावधान था। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 साल तक इसे रोक कर रखा और अब 'मल्टीप्लायर फैक्टर' को लागू कर झूठी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है।

गोद ली बच्ची को पीटकर हाईवे पर लावारिस छोड़ा

भोपाल से श्योपुर तक 400 किमी ले गए, मानव तस्करी की आशंका

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के एक दंपती ने ढाई साल की मासूम बच्ची को श्योपुर के पास छोड़ दिया। घटना 18 अप्रैल की है, लेकिन गुरुवार को श्योपुर पुलिस भोपाल आई और दंपती को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पुलिस को मानव तस्करी की भी आशंका है, उस पर जांच की जा रही है।

श्योपुर के टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे पर सोंईकलां के पास एक ढाई साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। कम उम्र के कारण बच्ची अपने घर का पता या माता-पिता का नाम नहीं बता पाई। पुलिस ने बच्ची को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने भी सोशल मीडिया पर बच्ची की पहचान के लिए कैंपेन शुरू किया था।

सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीरें देखने के बाद भोपाल की एक महिला ने श्योपुर संपर्क किया। दावा किया कि वह बच्ची की

केयर टेकर रही है। भोपाल के एयरपोर्ट रोड में रहने वाले आकाश और कृतिका नाम के दंपती ने इस बच्ची को गोद लिया था। बच्ची को जमकर पीटा जाता था।

कॉल करने वाली महिला ने स्वयं को भोपाल के लालघाटी का होना बताया था। महिला के दावों की तस्दीक के बाद श्योपुर के मानपुर थाने की पुलिस भोपाल पहुंची। बच्ची को फेंकने के लिए दंपती भोपाल से श्योपुर तक 400 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे थे।

केयर टेकर बोली - आकाश बच्ची को पीटता था- बच्ची की केयर टेकर बबीता ने बताया कि उन्होंने तीन महीने तक बच्ची को संभाला है। तस्वीर से उसकी पहचान करने के बाद उन्होंने ही श्योपुर पुलिस को सूचना दी। एयरपोर्ट रोड आसाराम चौराहा पर स्थित सेवा सदन के करीब कॉलोनी में रहने वाले आकाश के घर तक पुलिस को वह लेकर पहुंची थीं। वहां से पुलिस ने आकाश और उसकी पत्नी कृतिका को हिरासत में लिया।

दोनों को पुलिस साथ ले गई है। आकाश ने स्वीकार किया है कि बच्ची को उसी ने श्योपुर में छोड़ा था। बबीता का दावा है कि बच्ची को तीन महीने की थी तब आकाश और कृतिका लेकर आए थे। कहां से लाए, कैसे लाए, किसी को नहीं बताया। जबकि दोनों के पास पहले ही दो बच्चे थे। दोनों बच्ची को मारते और पीटते थे। बच्चों की देखरेख के लिए केयर टेकर को 20 हजार रुपए महीने की सैलरी पर रखा गया था।तीन महीने काम करने के बाद भी बबीता को सैलरी नहीं मिली तो उसने काम छोड़ दिया। वह उसकी विशेष देखरेख करती थी।

मानव तस्करी के एंगल पर भी पुलिस की जांच- श्योपुर पुलिस मामले में मानव तस्करी एंगल पर भी जांच कर रही है। दंपती के पास पहले से मौजूद बच्चों के संबंध में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी बच्ची को कहां से और कैसे लाए। क्या बच्ची की खरीद फरोख्त की गई है, इस संबंध में पुलिस दंपती से पूछताछ कर रही है।

ईंट-भट्टा मजदूर ने पुलिस को दी सूचना

मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार दुबे ने बताया कि सोंईकलां के पास एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ने बच्ची को हाईवे पर अकेले घूमते देखा था। मजदूर की सूचना पर तत्काल डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपनी सुरक्षा में लिया।

परिजन की तलाश में जुटी टीम

आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों से बच्ची का मिलान किया जा रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि यदि किसी को भी बच्ची के परिजनों के बारे में जानकारी मिले, तो वे तुरंत मानपुर पुलिस को सूचित करें।

संपादकीय

इसके नतीजे दूरगामी होंगे

देश में यह अपने ढंग का शायद पहला मामला है, जब याचिकाकर्ता ने सुनवाई करने वाले जज की निष्ठा पर ही सवाल खड़े करते हुए उन्हें केस से हटने को कहा और जज ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए तर्क दिया कि अदालत का कक्ष धारणाओं का मंच नहीं हो सकता। अगर कोर्ट बिना किसी ठोस कारण के इस मामले से हटती है तो इससे उन आरोपों को महत्व मिल जाएगा, जिनका कोई आधार नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि केजरीवाल मामले की सुनवाई वही जज करेंगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में याचिकाकर्ता की मंशा और अदालत के आदेश को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़ा है। जस्टिस शर्मा पूर्व में दिल्ली में आप सरकार के दौरान हुए कथित शराब घोटाले के मामले की सुनवाई कर रही हैं। जिनमें एक प्रमुख आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल अपने मामले की पैरवी खुद कर रहे हैं। इसी दौरान अपने बयान में उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की निष्ठा पर न केवल सवाल उठाए बल्कि सीधे तौर पर उन्हें सुनवाई से हटने को कहा। केजरीवाल का कहना था कि जस्टिस शर्मा के आरएसएस से सम्बन्ध हैं तथा उनके रिश्तेदार न्याय व्यवस्था से जुड़े लाभकारी पदों पर हैं। ऐसे में निष्पक्ष न्याय होने की संभावना नहीं है। हालांकि केजरीवाल के आरोप राजनीति से प्रेरित ज्यादा हैं, फिर भी उसमे आंशिक सच्चाई है। आम तौर पर जब भी किसी जज का केस से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है या फिर होने की संभावन लगती है तो वो स्वयं केस से अलग हो जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि शायद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा भी ऐसा ही कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले की सुनवाई वे ही करेंगी। क्योंकि अगर यह अदालत बिना किसी ठोस कारण के इस मामले से हटती है, तो इससे उन आरोपों को महत्व मिल जाएगा जिनका कोई आधार नहीं है। अपने आदेश में उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाओं में दिए गए तर्क अटकलों पर आधारित थे। अगर मैं इन्हें स्वीकार कर लूं, तो यह एक चिंताजनक मिसाल स्थापित करेगा। मैंने अपने सामने आए सभी सवालों पर निडर होकर फ़ैसला किया है। इस अदालत का चोगा आरोपों और इशारों के बोझ से दबाया नहीं जा सकता। यह अदालत जब भी ज़रूरत होगी, अपने लिए खड़ी होगी, भले ही यह मुश्किल क्यों न लगे। इस मामले से हटना समझदारी नहीं बल्कि ड्यूटी से मुंह मोड़ना और सरेंडर करने जैसा होगा। प्रथम दृष्ट्या जस्टिस शर्मा की बात सही लगती है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जज को सुनवाई से हटने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा सकता है। खासकर राजनेताओंसे जुड़े मामलों में। और जज इसी तरह दबाव में केस से हटते रहे तो पूरी न्याय प्रणाली ही गड़बड़ा जाएगी। हालांकि यह फैसला देकर जस्टिस स्वर्णकांता ने अपने लिए भी सवालों का घेरा खुद खड़ा कर लिया है। क्योंकि अगर वो शराब घोटाले में केजरीवाल को दोषी पाती हैं तो वो यह कह सकते हैं कि कोर्ट ने बदले की भावना से यह फैसला दिया। अगर केजरीवाल निर्दोष करार करार दिए जाते हैं तो कहा जा सकता है कि कोर्ट मानसिक दबाव में आ गई। ऐसे में अदालत के लिए यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। वैसे कोई कोर्ट नियम कायदों, तथ्यों, दस्तावेजों और तर्कों के आधार पर ही निर्णय देती है। इस मामले में भी सही निष्पक्ष न्याय ही अदालत की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को कायम रख सकेगा।

बसपा की सोशल इंजीनियरिंग खोलेगी सत्ता की राह

मायावती ने इस बार अपने पत्ते बेहद सावधानी से खोले हैं। उन्होंने 2027 के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में एक नया और तकनीकी मोड़ दिया है, जिसे 'एसआईआर' (मतदाता सूची पुनरीक्षण) अभियान से जोड़ा गया है। आम तौर पर पार्टियां चुनाव से ऐन पहले टिकट बांटती हैं, लेकिन बसपा ने पहले ही करीब 40–50 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि, अब इस रणनीति में अचानक बदलाव किया गया है। मायावती ने अब उन नेताओं को तवज्जो देने का फैसला किया है जिन्होंने एसआईआर अभियान के दौरान बूथ स्तर पर सक्रियता दिखाई। पार्टी का मानना है कि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थकों के नाम सुरक्षित रखने से जीते जाते हैं। मायावती ने करीब 15 हजार बूथ कमेटियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट का मकसद यह समझना है कि कहां उनके वोट बैंक में सेंध लगी है और कहां साजिश के तहत समर्थकों के नाम काटे गए।

नजरिया

संजय सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 'पीडीए' के नारे के साथ मिशन-2027 का बिगुल फूंक चुके हैं और सत्तारूढ़ भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी खामोश लेकिन बेहद मारक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पिछले कुछ समय से दो ध्रुवीय होती दिख रही थी, उसे मायावती एक बार फिर त्रिकोणीय बनाने की कवायद में जुट गई हैं। इस बार उनकी रणनीति सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जमीनी स्तर पर डेटा और 'सोशल इंजीनियरिंग' के घातक मिश्रण के साथ मैदान में उतर रही हैं। मायावती के लिए यह चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने और दलित राजनीति की धुरी को फिर से अपने पाले में लाने की बड़ी चुनौती है।

मायावती ने इस बार अपने पत्ते बेहद सावधानी से खोले हैं। उन्होंने 2027 के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में एक नया और तकनीकी मोड़ दिया है, जिसे 'एसआईआर' (मतदाता सूची पुनरीक्षण) अभियान से जोड़ा गया है। आमतौर पर पार्टियां चुनाव से ऐन पहले टिकट बांटती हैं, लेकिन बसपा ने पहले ही करीब 40-50 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि, अब इस रणनीति में अचानक बदलाव किया गया है। मायावती ने अब उन नेताओं को तवज्जो देने का फैसला किया है जिन्होंने एसआईआर अभियान के दौरान बूथ स्तर पर सक्रियता दिखाई। पार्टी का मानना है कि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थकों के नाम सुरक्षित रखने से जीते जाते हैं। मायावती ने करीब 15 हजार बूथ कमेटियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट का मकसद यह समझना है कि कहां उनके वोट बैंक में सेंध लगी है और कहां साजिश के तहत समर्थकों के नाम काटे गए। जो पदाधिकारी इन कटे हुए नामों को दोबारा जुड़वाने और बूथ को मजबूत करने के मोर्चे पर सफल रहे हैं, उन्हीं की दावेदारी अब टिकट के लिए पुख्ता मानी जाएगी।

बसपा की इस नई रणनीति के केंद्र में वह 'सोशल इंजीनियरिंग' है, जिसने 2007 में पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंचाया था। मायावती एक बार फिर 'दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम' गठजोड़ को जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी समीकरणों के बीच मायावती यह समझ चुकी हैं कि केवल एक वर्ग के भरोसे सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए उन्होंने हर विधानसभा सीट पर चार-चार दावेदारों का पैनल तैयार करवाया है। इन दावेदारों को उनकी जातीय पकड़ और स्थानीय समीकरणों के आधार पर परखा जा रहा है। मायावती ने मंडल और जोनल कोऑर्डिनेटरों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे जातियों के गणित की सटीक रिपोर्ट दें। अगर किसी सीट पर दलित वोटों के साथ मुस्लिम या ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, तो वहां उसी समाज के मजबूत चेहरे को तलाशा जा रहा है। यह प्रक्रिया काफी गहरी है, जिसमें पहले क्षेत्र प्रभारी बनाया जाता है और फिर उसकी सक्रियता के आधार पर उसे प्रत्याशी घोषित किया जाता है।

मायावती का दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां बसपा का आधार हमेशा से मजबूत रहा है, वहां के समीकरणों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मायावती ने खुद संभाली है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि पार्टी इस बार किसी बड़े दल से गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मानना है कि गठबंधन से उनके वोट दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों के वोट बसपा को नहीं मिलते। ऐसे में अपने पारंपरिक वोट बैंक को सहेजकर रखना और उसमें दूसरे वर्गों को जोड़ना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। मायावती अब उन बूथों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जहां पिछले चुनावों में बसपा का प्रदर्शन गिरा था। वह खुद जिलों से आने वाली एक-एक रिपोर्ट की समीक्षा कर रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं, उन्हें दोबारा हर हाल में जुड़वाया जाए।

इस पूरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह संदेश है जो मायावती अपने कार्यकर्ताओं को दे रही हैं। वह लगातार बैठकों में इस बात का जिक्र कर रही हैं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच चल रही तकरार के बीच मायावती खुद को एक गंभीर और अनुशासित विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। वह जानती हैं कि 2027 में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उन छोटी जातियों और समुदायों से होकर गुजरता है जो फिलहाल मुख्यधारा की राजनीति में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके टिकट वितरण में इस बार जातियों की केमिस्ट्री पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एसआईआर अभियान से हुए नफे-नुकसान का आकलन कर उम्मीदवारों के चयन की यह पद्धति उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग है, जो यह दर्शाता है कि मायावती अब पुरानी शैली को आधुनिक चुनावी प्रबंधन के साथ जोड़ रही हैं।

हालांकि, राह इतनी आसान भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के लिए भाजपा और सपा दोनों ने ही बड़ी सेंधमारी की है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नए युवा चेहरों ने भी दलित राजनीति में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में मायावती का पुराना 'सोशल इंजीनियरिंग' फॉर्मूला कितना कारगर होगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन मायावती का इतिहास रहा है कि वह जब भी खामोश होती हैं, तो किसी बड़े सियासी धमाके की तैयारी में होती हैं। उनके पास अपना एक समर्पित कैडर है जो आज भी उनके एक इशारे पर लामबंद हो जाता है। 2007 के करिश्मे को 2027 में दोहराने के लिए उन्होंने संगठन के ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ब्राह्मण और मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर मैदान में उतारने की तैयारी यह संकेत देती है कि बसपा इस बार किसी भी हाल में चुनावी मुकाबले को दोतरफा नहीं होने देगी।

बहरहाल, 2027 का चुनाव बसपा के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। मायावती की यह सूक्ष्म रणनीति, जिसमें बूथ लेवल की रिपोर्टिंग से लेकर जातीय समीकरणों का जटिल जाल बुना गया है, विपक्षी खेमों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। क्या मायावती फिर से वही पुराना जादू चला पाएंगी? क्या एसआईआर अभियान के जरिए तैयार की गई उम्मीदवारों की नई फौज बसपा की नैया पार लगा पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय की रैलियों और चुनावी माहौल में मिलेगा। फिलहाल तो हाथी अपनी मदमस्त चाल से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दिख रहा है, और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर यूपी की सियासत का सबसे चर्चित अध्याय बनने की ओर अग्रसर है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसका एक ही लक्ष्य है सत्ता के शिखर पर बसपा का दोबारा परचम लहराना।

काली बैंक के अंधेरे से 'धोड़ी बैंक' के उजाले तक

आत्मनिर्भरता

निलेश देसाई

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

झाबुआ के पथरीले रास्तों और आदिवासी अंचलों में एक समय ऐसा था जब सूरज ढलने के बाद केवल रात का अंधेरा ही नहीं, बल्कि कर्ज का काला साया भी गहरा जाता था। यहाँ गरीबी केवल फटे हुए कपड़ों या खाली थाली का नाम नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी नियति बन चुकी थी जिससे निकलना नामुमकिन लगता था। लेकिन आज, उसी झाबुआ की माटी से एक ऐसी गूँज सुनाई दे रही है जिसने 'काली बैंक' के शोषणकारी तंत्र को उखाड़ फेंका है। यह कहानी है 'धोड़ी बैंक' (सफेद बैंक) की और उन 6,000 से अधिक महिलाओं की, जिन्होंने संगठित होकर गरीबी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और रू. 2.5 करोड़ के वित्तीय साम्राज्य की नींव रखी है।

अस्सी के दशक में झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में सूदखोरी की व्यवस्था को स्थानीय भाषा में 'काली बैंक' कहा जाता था। नाम के अनुरूप ही इसका काम भी काला और डरावना था। आदिवासी समाज में जब किसी को बीमारी, शादी-ब्याह या खेती के लिए बीज-खाद की तत्काल आवश्यकता होती, तो उनके पास इन साहूकारों के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

यहाँ ऋण देने का गणित शोषण की पराकाष्ठा था। अगर कोई 100 रुपये कर्ज मांगता, तो उसे हाथ में केवल 90 रुपये मिलते थे–10 रुपये अग्रिम ब्याज के रूप में पहले ही काट लिए जाते थे। लेकिन उसे लौटाने 110 रुपये पड़ते थे। वसूली का आलम यह था कि साहूकार सुबह 5 बजे ही दरवाजे पर दस्तक दे देते थे। पैसे न होने पर मवेशी, बर्तन या पुश्तैनी जमीन तक गिरवी रख ली जाती थी। यह व्यवस्था गरीबी को कम करने के बजाय उसे एक अंतहीन चक्रव्यूह में बदल देती थी, जहाँ पिता का कर्ज बेटे के कंधों पर विरासत में मिलता था।

इस घुटन भरे माहौल में बदलाव की पहली किरण 1980 के दशक के उत्तरार्ध (1987) में दिखाई दी। जुनाखेड़ा गांव में एक छोटी सी चौपाल सजी, जहाँ ग्रामीणों ने अपनी नियति को बदलने का ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे साहूकारों के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपना खुद का 'ग्राम कोष' बनाएंगे।

यही 'ग्राम कोष' आगे चलकर 'धोड़ी बैंक' (सफेद बैंक) कहलाया। इसकी शुरुआत महज़ रू. 2,000 के सामूहिक अंशदान से हुई थी। सिद्धांत सरल था: 'गांव का पैसा, गांव के लोगों के लिए और गांव के ही नियंत्रण में।' यहाँ ब्याज दरें कम थीं, प्रक्रिया पारदर्शी थी और सबसे बड़ी बात–इसमें कर्जदार का सम्मान था। धीरे-धीरे यह मॉडल आसपास के गांवों में फैल गया और भविष्य की 'महिला शक्ति' की मजबूत नींव बना। धोड़ी बैंक ने रास्ता दिखाया, लेकिन उसे एक राष्ट्रव्यापी मिसाल बनाने का श्रेय झाबुआ की ग्रामीण महिलाओं को जाता है। समय के साथ पुरुषों द्वारा शुरू की गई इस पहल की कमान महिलाओं ने थामी और जन्म हुआ 'महिला शक्ति संघ' का। 1987 में बोया गया वह छोटा सा बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है-

1. आज इस संगठन से 40 से अधिक गांवों की 6,000 से ज्यादा महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं।
2. वर्तमान में इस समूह द्वारा लगभग 2.5 करोड़ की राशि ऋण के रूप में वितरित की जा चुकी है।
3. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 2.5 करोड़ केवल सरकारी अनुदान नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं की अपनी मेहनत की कमाई और चंद रुपयों की छोटी-छोटी बचतों का परिणाम है। यह अब एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुका है।

इस 2.5 करोड़ के वितरण ने गांवों में स्वरोजगार की ऐसी बाढ़ ला दी है कि महिलाएं अब केवल गृहणी नहीं, बल्कि कुशल प्रबंधक और उद्यमी बन चुकी हैं।

केस स्टडी 1: पलायन को मात देती कमला बाई- काचबी गांव की कमला बाई की कहानी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक, कमला बाई और उनका परिवार पेट पालने के लिए हर साल गुजरात पलायन करता था। वहाँ वे बंधुआ मजदूरी जैसी कठिन स्थितियों में काम करते थे। लेकिन महिला शक्ति संघ से जुड़ने के बाद उन्होंने रू. 15,000 का ऋण लिया और अपने छोटे से खेत में उन्नत सब्जी की खेती शुरू की। आज कमला बाई का पलायन पूरी तरह रुक चुका है। वे कहती हैं, 'पहले कर्ज का नाम सुनकर डर लगता था क्योंकि वह हमें डुबोता था, लेकिन आज का कर्ज हमें आगे बढ़ाता है। अब हम साहूकार के घर नहीं, बल्कि बैंक और बाजार खुद जाते हैं।'

केस स्टडी 2: मीना बाई के सपनों की उड़ान- मीना बाई कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी कर बमुश्किल दो वक्त की रोटी जुटा पाती थीं। संघ के सहयोग से उन्होंने ऋण लेकर एक सिलाई मशीन खरीदी और प्रशिक्षण लिया। आज वे न केवल गांव के कपड़े सिलती हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म तैयार करने का ठेका भी लेती हैं। महीने की 8,000 से 10,000 की आय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी है। उनकी बेटी अब शहर के कॉलेज में पढ़ रही है–एक ऐसा सपना जो 'काली बैंक' के दौर में देखना भी असंभव था।

महिला शक्ति संघ का प्रभाव केवल बैंक बैलेंस या तिजोरियों तक सीमित नहीं रहा। इन महिलाओं ने ग्रामीण समाज की जड़ों में जमी कुरीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया है:

1. फिजूलखर्ची पर लगाम: शादियों और मृत्यु भोज जैसे सामाजिक आयोजनों में होने वाले अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए संघ ने सामूहिक निर्णय लिए हैं। इससे परिवारों पर कर्ज का बोझ कम हुआ है।

अड़जी-पड़जी परंपरा: खेती में एक-दूसरे की मदद करने की प्राचीन परंपरा 'अड़जी-पड़जी' को फिर से जीवित किया गया है। इससे मजदूरों पर होने वाला खर्च बचता है और गांवों में आपसी भाईचारा बढ़ता है।

पारिवारिक समृद्धि: इन सामूहिक प्रयासों और बचतों के कारण प्रत्येक परिवार अब सालाना 20,000 से 30,000 की अतिरिक्त बचत कर पा रहा है।

2. घरेलू हिंसा और विवाद: गांव के छोटे-मोटे झगड़े या घरेलू विवाद अब पुलिस स्टेशन या अदालतों में जाने के बजाय संघ की बैठकों में महिलाओं द्वारा आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। झाबुआ की यह गौरवगाथा महज एक वित्तीय मॉडल की सफलता नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की वापसी की कहानी है। 1987 में एक छोटी सी बैठक से शुरू हुआ यह कारवां आज 6,000 महिलाओं की वह ताकत बन चुका है, जिसने गरीबी को नियति मानने से इनकार कर दिया।2.5 करोड़ का वित्तीय लेनदेन यह साबित करता है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को सही मंच, पारदर्शी व्यवस्था और संसाधन मिलें, तो वे किसी भी बड़े कॉरपोरेट हाउस की तरह प्रबंधन कर सकती हैं। 'काली बैंक' की बेड़ियों को तोड़कर 'धोड़ी बैंक' के माध्यम से महिला शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि गरीबी का स्थायी इलाज केवल बाहरी मदद नहीं, बल्कि सामुदायिक एकजुटता और अटूट इच्छाशक्ति है। आज झाबुआ की ये महिलाएं केवल अपने घर की अर्थव्यवस्था नहीं चला रहीं, बल्कि वे महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के उस सपने को धरातल पर उतार रही हैं जहाँ गांव अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र और आर्थिक रूप से पूर्णतः सक्षम है। यह आंदोलन देश के अन्य पिछड़े अंचलों के लिए एक 'प्रकाश स्तंभ' है, जो यह संदेश देता है कि जब महिलाएं संगठित होती हैं, तो वे केवल अपना भविष्य नहीं, बल्कि पूरे समाज का भूगोल और इतिहास बदल देती हैं। झाबुआ की इन 'शक्ति पुंजों' को हमारा नमन।

प्रेम, अपराध और सामाजिक विघटन का गठजोड़

महिला अपराध

एकता शर्मा

(लेखक एवं सामाजिक विश्लेषक)

कुछ महीनों में ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आई, जिसमें पति की हत्या में पत्नियां शामिल पायी गई। उन्होंने ये वारदात अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। ऐसे अपराध सिर्फ इंदौर जैसे महानगरों में ही नहीं सिंगरौली और भिंड जैसे छोटे शहरों के गांव तक में हो रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनम, रूबी, उमा और प्रियंका जैसी घटनाएं केवल चार नाम नहीं हैं, बल्कि ये एक चेतावनी है कि समाज में कहीं न कहीं रिश्तों की नींव कमजोर हो रही है। यदि इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो यह प्रवृत्ति और भी खतरनाक रूप ले सकती है। जरूरत है कि इस विषय को सनसनी के रूप में नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में देखें और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करें।

समाज में अपराधों की प्रकृति समय के साथ बदलती रही है, लेकिन जब प्रेम, विश्वास और वैवाहिक संबंध जैसे पवित्र माने जाने वाले तत्व ही अपराध की जड़ बन जाएँ, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। प्रेमी के साथ साजिश रचकर पति की हत्या करवाने वाली इंदौर की सोनम रघुवंशी, भिंड की रूबी, सिंगरौली की उमा वैश्य और धार की प्रियंका पुरोहित जैसी घटनाएं केवल अलग-अलग आपराधिक मामले नहीं हैं। बल्कि यह एक गहरी सामाजिक विकृति का संकेत हैं। इन मामलों में एक समान सूत्र यह है कि इन महिलाओं ने अपने प्रेम संबंधों को पाने के लिए अपने ही पतियों की हत्या का षड्यंत्र रचा। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, रिश्तों और नैतिकता के पतन का भी द्योतक है। ये न तो फिल्मों का प्रभाव है और न सामाजिक बदलाव का संकेत। यह एक अलग तरह है, जिसमें कानून का भय गौण सा हो गया। पतियों की हत्याओं में पत्नियों के शामिल होने की घटनाओं को केवल व्यक्तिगत अपराध मानकर छोड़ देना आसान है। लेकिन, इनके पीछे छिपे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों को समझना अधिक आवश्यक है। सबसे पहले सवाल उठता है, कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, जहां विवाह जैसे रिश्तों में बंधी महिलाएं अपने जीवनसाथी की हत्या तक करने या करवाने की साजिश में शामिल हो जाती हैं। इसका बड़ा कारण हमारे समाज में विवाह की पारंपरिक व्यवस्था और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच का टकराव है। कई बार विवाह सामाजिक दबाव, परिवार की इच्छा या आर्थिक कारणों से होता है, जिसमें भावनात्मक संतुष्टि का अभाव रह जाता है। ऐसे में यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भावनात्मक या शारीरिक संबंध बनते हैं, तो वह व्यक्ति 'मुक्ति' का प्रतीक लगने लगता है। हालांकि, यह स्थिति केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। पुरुष भी इस प्रकार के अपराध करते हैं। लेकिन, जब महिलाएं इस तरह की साजिशों में शामिल होती हैं, तो समाज के लिए यह अधिक चौंकाने वाला तो होता ही है। क्योंकि, पारंपरिक दृष्टिकोण में महिलाओं को संवेदनशील, सहनशील और परिवार को जोड़कर रखने वाली भूमिका में देखा जाता रहा है। इसलिए जब वही महिला अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल होती है, तो यह सामाजिक सोच को झकझोर देता है। इन घटनाओं का एक दूसरा पहलू यह भी है कि आज के दौर में फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्तों और प्रेम की एक विकृत छवि भी सामने आ रही है। 'अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना' जैसे विचारों को कई बार रोमांटिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे युवा मन प्रभावित होते हैं और वे वास्तविक जीवन की जटिलताओं को समझे बिना अतिवादी कदम उठा लेते हैं। जब भावनाएँ तर्क पर हावी हो जाती हैं, तब अपराध की जमीन तैयार होती है।

इसके अलावा, सामाजिक संरचना में तेजी से हो रहे बदलाव भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। एक ओर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, शिक्षा और करियर में आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक रिश्तों की अपेक्षाएं अब भी वैसी ही बनी हुई हैं। यह द्वंद्व कई बार मानसिक तनाव और असंतोष को जन्म देता है। यदि इस स्थिति में संवाद और समझ का अभाव हो, तो व्यक्ति गलत दिशा में कदम उठा सकता है। इन मामलों में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अपराध अकेले नहीं किया गया, बल्कि प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा गया। इसका मतलब यह है कि यह केवल भावनात्मक आवेग नहीं, बल्कि योजनाबद्ध अपराध है। यह दर्शाता है कि अपराध करने से पहले नैतिकता और कानून की सीमाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या इन महिलाओं को यह विश्वास था कि वे बच जाएंगी या फिर उनके लिए उस समय अपने प्रेम संबंध को बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने परिणामों की परवाह ही नहीं की! इस समस्या का समाधान केवल कड़े कानून या सजा में नहीं है। क्योंकि, ये अपराध पहले से ही गंभीर दंडनीय हैं। असली समाधान सामाजिक और मानसिक स्तर पर बदलाव में है। सबसे पहले, विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध न मानकर एक भावनात्मक साझेदारी के रूप में समझने की आवश्यकता है। यदि किसी रिश्ते में असंतोष है, तो उसके समाधान के लिए संवाद, परामर्श और कानूनी विकल्प मौजूद हैं। हत्या जैसे अपराध को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही, समाज में रिश्तों और प्रेम को लेकर एक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। युवाओं को यह समझाना जरूरी है कि प्रेम का अर्थ अधिकार या स्वामित्व नहीं होता, और न यह किसी अन्य के जीवन को समाप्त करने का कारण बन सकता है। मीडिया और मनोरंजन उद्योग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसे विषयों को प्रस्तुत करते समय संवेदनशीलता बरतनी होगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

शांति वार्ता की सर्जरी

व्यंग्य

मृदुल कश्यप

लेखक व्यंग्यकार हैं।

ऑपरेशन टेबल पर प्रस्ताव रख दिया गया है। जैसी की परंपरा है, ऑपरेशन करने से पहले मरीज से उसका नाम पूछा जाता है।

इसलिए उससे जब नाम पूछा गया तो वह कराहते हुए बोला शांति। पूरा नाम शांति वार्ता।

तीन लोग कमरे में घुसते हैं और और वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों को फटकार लगा कर बाहर भगा देते है। उनमे से एक के बाल सुनहरे थे था। दूसरा दाढ़ी वाला था औरसिर पर कपड़ा बांध रखा था। तीसरे के सर पर सफेद बाल थे और उसने गहरे रंग का सूट और टाई पहन रखा था। वह क्लीन शेवड था। उनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी था।

क्या मै भी बाहर जाऊं ? चौथे आदमी ने (जिसने जाली टोपी पहन रखी थी) सर झुका कर अदब से पूछा हाँ। तुम्हारा काम यही तक था - सुनहरे बाल वाले ने कंधे उचकाते हुए कहा।

यह ले जाओ और इसे बाहर बाँट देना - तीसरे ने उसे रुई का एक बण्डल देते हुए कहा। वो तीसरा यहाँ क्या कर रहा हैं ? दूसरे ने पहले से पूछा। वे मुझे असिस्ट कर रहे हैं - सुनहरे बालो वाला बोला। पर यह मुझे पसंद नहीं है ? क्या मैं भी बुला लूँ अपने साथी को ? उस मिचमिची आँखों वाले को ..! - कहकर सुनहरे बालो वाला बड़े अजीब ढंग से। हँसते हुए उसने तीसरे की तरफ आँखों से कोई इशारा किया।

क्या मैं बाहर जाऊं सर ? वैसे भी मुझे जॉर्डन जाना है! तीसरा जल्दी से अपना बेग उठा कर बोला।

नहीं तुम यही रुको - सुनहरे बालो वाला बोला यह आप लोग क्या कर रहे है ? कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। मुझे तो एक शरीफ आदमी ने यहाँ बुलाया है। और आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा - शांति बोला।

उनका सिर्फ नाम शरीफ है समझे मिस्टर शांति -सुनहरे बालो वाला बोला।

उधर बाहर जाली टोपी वाले ने ऑपरेशन थियेटर के बाहर खड़े लोगो को रुई बाँट दी। और हिदायत देता हुआ बोला - सब लोग अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। ऑपरेशन बेहद जटिल है। जोर जोर से कान फोड़ू आवाजे आएगी पर आप लोग ज्यादा ध्यान मत देना। इसे नार्मल ही समझना।

उधर अन्दर ऑपरेशन थियेटर में शांति ने पूछा - यह क्या कर रहे है आप लोग। क्या मुझे बेहोश नहीं करेंगे ? मेरा ऐसे ही ऑपरेशन करेंगे।

नहीं , एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारा लाइव रेस्पॉन्स चाहिए। अगर बेहोश कर देंगे तो कैसे मिलेगा। सिर पर कपड़ा बांधे हुए उस व्यक्ति ने कहा डोंट वरी। यू आर इन सेफ हैण्ड - पहले के पीछेखड़ा तीसरा बोला।

पर आप जो है दस्ताने पहन रहे हैं उसमें तीखे, लम्बे नाखून लगे हैं। और कोई दूसरे औजार नही लिए।

हां। सुनहरे बालो वाला अपना सर हिलाता हुआ बोला -हम ऐसे ही सर्जरी करते हैं। इतना कहकर सुनहरे बालो वाले ने शांति वार्ता पर एक मिसाइल का प्रयोग। शांति वार्ता बिलबिलाने लगी। तभी तीसरा बम बरसाने लगा। यह देख कर दूसरा ने अपना ड्रोन चलाया। शांति वार्ता जोर जोर से चिल्लाने लगी।

वह चिल्लाई - बचाओ , बचाओ।

यह सुनकर तीनो ने जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगा दिया। और अपने काम में जुट गए।

बाहर निकलने से पहले सुनहरे बालो वाले ने तीसरे को इशारा किया। उसने शांति को उल्टा लिटा दिया। सुनहरे बालो वाले ने जेब से एक खंजर निकाला और उसेशांति वार्ता की पीठ में भोंक दिया। ऑपरेशन थियेटर से सुनहरे बालो वाला सबसे पहले निकला और वहां खड़े जाली टोपी वाले से चौथे से बोला - इसे आईसीयू में पहुंचा दो। फिर वहां खड़े दूसरे लोगो से बोला -- आई एम टायर्ड, आई नीड टू रेस्ट। बाकीडिटेल मेरे सोशल मीडिया पर देख लीजिए।

थोड़ी देर बाद पहले और दूसरे ने मीडिया में लगभग एक जैसी पोस्ट करी - मैंने अपने हिस्से की सर्जरी कर दी है पर साथी डॉक्टर ने को ऑपरेट नही किया।

पंचायतें सशक्त होंगी तभी सशक्त होगा ग्रामीण भारत

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं।

आधुनिक भारत में इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा में महात्मा गांधी ने विशेष बल दिया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और सशक्त गांव ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों ने पंचायती राज को संस्थागत रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला, उसने भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस संशोधन ने तीन-स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) को कानूनी मान्यता दी। साथ ही, ग्राम सभा को आधारभूत इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जिससे प्रत्येक नागरिक को सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिला। यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करती है बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों को भी सुनिश्चित करती है।

हर वर्ष 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस गहरी जड़ का उत्सव है, जो गांवों की मिट्टी में बसती है और आम नागरिक की भागीदारी से सशक्त होती है। यह दिवस हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 लागू होकर 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ और भारत के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को एक नया संवैधानिक आधार मिला। यह वह पड़ाव था, जिसने लोकतंत्र को केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित न रखकर उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। यही दर्शन पंचायती राज व्यवस्था के मूल में निहित है। यह प्रणाली शासन को केंद्र से हटाकर जमीनी स्तर तक ले जाती है, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं तय कर सकते हैं। यह केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है, जिसमें ग्रामीण समाज स्वयं अपने विकास का मार्ग निर्धारित करता है।

पंचायती राज की अवधारणा भारत में नई नहीं है। प्राचीन काल से ही गांवों में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा रही है, जिसे 'ग्राम गणराज्य' के रूपमें जाना जाता था। आधुनिक भारत में इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा में महात्मा गांधी ने विशेष बल दिया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और सशक्त गांव ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों ने पंचायती राज को संस्थागत रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला, उसने भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस संशोधन ने तीन-स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) को कानूनी मान्यता दी। साथ ही, ग्राम सभा को आधारभूत इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जिससे प्रत्येक नागरिक को सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिला। यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करती है बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों को भी सुनिश्चित करती है। इस संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आरक्षण व्यवस्था है, जिसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष रूप से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। आज देशभर में लाखों महिलाएं पंचायतों में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं, जो सामाजिक परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप है, जिसने ग्रामीण समाज की संरचना को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का महत्व केवल ऐतिहासिक स्मरण तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि हम लोकतंत्र को कितना गहराई तक ले जा पाए हैं। पंचायतें आज ग्रामीण विकास की धुरी बन चुकी हैं। स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल योजनाओं को लागू करती हैं बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अनुकूलित भी करती हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है, जब भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में पंचायतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल युग में पंचायतें अब केवल पारंपरिक संस्थाएं नहीं रही बल्कि तकनीक-संचालित प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विकसित हो रही हैं। ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन योजना निर्माण और पारदर्शिता के नए आयाम इस परिवर्तन को और गति दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारासंचालित ई-ग्रामस्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसी प्रकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे विवाद कम हो रहे हैं और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये पहलें केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के महत्वपूर्ण साधन हैं।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाता है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। ये पुरस्कार केवल उपलब्धियों का सम्मान नहीं बल्कि नवाचार, पारदर्शिता और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का माध्यम हैं। गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में पंचायतों की उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयास किस प्रकार राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकते हैं। हालांकि, पंचायती राज व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक क्षमता का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और तकनीकी ज्ञान की सीमाएं इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल नीतिगत सुधारों से ही नहीं बल्कि सामुदायिक जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से भी संभव है। जब तक ग्रामीण नागरिक स्वयं अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक पंचायती राज की वास्तविक शक्ति पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में न देखा जाए बल्कि उन्हें विकास के साझेदार के रूप में स्वीकार किया जाए। उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन, तकनीकी प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन प्रदान करना समय की मांग है। साथ ही, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमें यही संदेश देता है कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है बल्कि यह निरंतर भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी का नाम है। पंचायतें इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करती हैं। वे न केवल समस्याओं का समाधान करती हैं बल्कि एक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन भी करती हैं। वास्तव में मजबूत गांव ही मजबूत भारत की नींव हैं। यदि पंचायतें सशक्त होंगी तो ग्रामीण भारत सशक्त होगा और जब ग्रामीण भारत सशक्त होगा, तब ही 'विकसित भारत' का सपना साकार हो सकेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एक ऐसे भविष्य की संभावनाओं का आह्वान है, जहां लोकतंत्र वास्तव में जनता के हाथों में हो और हर नागरिक अपने विकास का भागीदार बने।

कागद लेखी और आंखन देखी

पंचायत दिवस विशेष

श्याम बोहरे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

पंचायतें हमारे देश में बहुत पहले से रहीं हैं,मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'पंच परमेश्वर'के माध्यम से पंचायत की न्यायप्रियता का आदर्श जानते आये हैं। पहले की पंचायतें अधिकतर स्थानीय विवाद ही सुलझाया करती थीं,उनके पास कानूनी ताकत नहीं होती थी परन्तु समाज में पर्याप्त रसूख था। पहले की पंचायतें आर्थिक रुप से आज की पंचायतों के मुकाबले मजबूत नहीं थीं। पंचायतें अधिकतर गांव के बलशाली सामंती दबाव में काम करतीं थीं, महिलाओं का प्रतिनिधत्व दूर की कौड़ी था इसी तरह गरीब दलित प्रतिनिधत्व अपवाद स्वरुप ही रहा होगा , कुल मिलाकर बहुत ही अनौपचारिक तरीके से काम करती थीं।

24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जिसमें विकेन्द्रित स्वशासन के माध्यम से गांव के विकास के लिए कानूनी व्यवस्था की गई। पूरे देश में त्रिस्तरीय (जिला, जनपद और ग्राम पंचायत) पंचायत राज स्थापित किया गया। संविधान में संशोधन कर पंचायतों को नियमित, स्थाई ,आर्थिक और कानूनी रुप से मजबूत किया गया, पूरी कार्यप्रणाली को औपचारिक ढांचे में समाहित किया गया, जिससे जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन स्थापित हो सके, निश्चित ही सराहनीय कदम है,इस लोकतांत्रिक पहल के लिए राजीव गांधी बधाई के पात्र हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को हर 5 साल में पंचायतों का चुनाव कराना जरुरी हो गया,राज्य की आय का निश्चित अनुपात पंचायतों को देना जरुरी हो गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में दिये गये 29 विषयों से सम्बन्धित विभागों के धन, कार्य और कर्मचारी सौंपे गये, जिससे पंचायतें स्वशासन की स्वायत्त ईकाई की तरह काम कर सकें। संविधान की धारा 40 के अनुसार 'राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्रधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाई के रुप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।' संविधान की धारा 243 में पंचायतों के गठन, संरचना,स्थानों का आरक्षण, अवधि, सदस्यता के लिए निरर्हताएं, शक्तियां,प्राधिकार और उत्तरदायित्व, कर (टेक्स) अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन,लेखाओं के आडिट, निर्वाचन, आदि विषय विस्तार से दिए गए हैं इनमें 243 छ. (क) में पंचायत का महत्वपूर्ण काम दिया गया है जिसके अनुसार पंचायतों का काम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना है।

यह तो रहा कागद की लेखी - पंचायतों का औपचारिक कानूनी और घोषित स्वरुप। अब अनुभव और आंखन देखी भी देख लेते हैं। पंचायत राज दिवस पर पहले यह जान लें कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जो मजबूत होते हैं उनका दिवस नहीं मनाया जाता। पुलिस थाना दिवस, अखाड़ा दिवस,कोर्ट-कचहरी दिवस, इसी तरह से शिक्षक दिवस मनाते हैं लेकिन थानेदार दिवस और पहलवान दिवस मनाने की जरुरत नहीं होती। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस इसीलिए मनाया जाता है यह मैं नहीं कहना चाहता।

औपचारिक और लिखित रुप में तो पंचायतें स्वशासन की स्वायत्त इकाइयां हैं, लेकिन व्यवहार में पंचायतें शासन की कार्यपालिका की अधीनस्थ इकाइयों से अधिक हैसियत नहीं रखतीं। जो इससे असहमति रखते हों वे मध्य प्रदेश की 23600 ग्राम पंचायतों में से केवल आधा प्रतिशत से भी कम 100 पंचायतें ऐसी दिखा दें, जो शासन के आदेशों के अलावा या मंजूरी के बिना कोई नया काम कर रहीं हों, उन कामों में पंचायत को आवंटित राषि का उपयोग केवल ग्राम पंचायत की अनुमति से कर पा रहीं हों। बिना रिश्वत दिए कार्यालयों से अपना काम करा पा रहीं हों। रिश्वत वाला यह सवाल जब सरपंचों से करता तो कुछ सरपंच जोष में आकर कहते कि वे रिश्वत नहीं देते, लेकिन दस साल के दौरान एक भी ऐसे सज्जन नहीं मिले जो पांच छह सवालों से आगे टिक पाये हों, अंत में कहते कि प्यार - मोहब्बत और अपनी खुशी से आदर सत्कार में भेंट तो हर जगह चलती है। यह पूछने पर कि यह प्यार, मोहब्बत और आदर सत्कार एकतरफा ही क्यों होता है? तो हंस कर कहते कि आप तो बाल की खाल निकालने पर तुल गए। यदि इस व्यवस्था में भी पंचायतों को कोई स्वशासन की स्वायत्त ईकाई माने तो कोई क्या कर सकता है? इसे इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि कोई यह बताये कि पंचायत द्वारा पारित कितने विधिसम्मत प्रस्ताव अफसरों ने नामंजूर कर दिये और पंचायतें उन्हें कभी लागू नहीं कर पाईं। इसके बरक्स अफसरों के कितने आदेश न मानकर पंचायतें कितने काम कर सकीं हैं ? जबकि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वाराज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत और ग्राम सभा भी एक निगमित निकाय है ,जिसका स्वायत्त उत्तराधिकार है , जिसकी एक मुद्रा होती है, जो वाद (मुकदमा) कर सकती है और जिस पर वाद किया जा सकता है मतलब यह कि पंचायत और ग्राम सभा कानून द्वारा स्थापित ईकाई है जिसके विधि सम्मत फैसलों के खिलाफ काम करने वाले पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कितने मामलों में पंचायतों ने इस कानूनी प्रावधान का उपयोग किया ? एक उदाहरण जरुर है, दतिया जिले की हेमतपुरा ग्राम पंचायत ने पंचायत के प्रस्ताव के खिलाफ काम करने पर जिले के कलेक्टर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। जिले के कलेक्टर को ग्वालियर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दोषी पाते हुए सजा सुनाते हुए 5000 रुपये का जुर्माना किया और उन्हें वहां से तत्काल बदलने का आदेश शासन को दिया जिसका शासन ने तुरन्त पालन किया। उस समय अखबारों ने न्यायालय के इस फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, इसके बावजूद भी प्रदेश की पंचायतें इस तरह के काम नहीं कर सकीं जिससे अफसर पंचायतों के कानून रौंदते रह ,और पंचायतें बेबस बनी रहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी यह समझ गलत साबित हो कि पंचायतों में कानूनों और नियमों को ताक पर रखते हुए बेईमानी नियमों से अधिक स्थापित हो गई है।

अफसरों की लापरवाही के दो उदाहरण देखते हैं जिसमें अफसरों को कुछ भी गलत नजर नहीं आता। 2002 की बात है पन्ना जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालिका अधिकारी ने एक व्यक्ति (जिसे वे सरपंच मान रहे थे) से कहा कि दो तालाबों के लिए 5 लाख रुपयों का प्रस्ताव अभी ले आओ। उन सज्जन ने तुरन्त एक कागज पर प्रस्ताव लिखकर साहब को दिया, साहब ने तुरन्त उसे बिना जांचे ही स्वीकृत कर दिया। जब वे सज्जन चले गए तो मैंने कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैं आपका वरिष्ठ अधिकारी नहीं हूं, नहीं तो मैं आपको इसी समय नौकरी से निकाल देता। उन्होंने पूछा कि उनने क्या अपराध किया है? मैंने उनसे पूछा कि कानून के अनुसार जिले की पंचायतें काम करें यह सुनिश्चित करना और उसके लिए मार्गदर्शन करते हुए व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी है या नहीं? जाहिर है वे सहमत थे। पंचायत का प्रस्ताव पंचायत कार्यालय में सभी चुने हुए (15 से 20) वार्ड मेम्बरों की सलाह के अनुसार होना चाहिए या केवल सरपंच की सहमति से? उनका जवाब था कि चुने हुए सभी वार्ड मेम्बरों की बैठक में किये गये विचार विमर्श से। अभी जो प्रस्ताव आपने मंजूर किया वह तो यहीं आपके सामने लिखा गया वह कानून के अनुसार था ? उन्होंने चेक कर कहा, अरे.... ऐसा है ? जिन सज्जन ने अपनी मूंछें सम्हालते हुए आपके सामने विमला देवी के दस्तखत किये , महिला के दस्तखत पुरुष कर रहा है यह कैसे नहीं देखा आपने ? क्या यह अपराध नहीं है ? उनका कहना था कि इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उनसे पूछा यदि इस पूरे प्रकरण की फिल्म बनी होती और आपसे पूछताछ होती तो आप क्या कहते ? बहुत ही इत्मीनान से उन्होंने कहा कौन इतनी बारीकी से देखता है? काम जल्दी हो इसलिए शॉर्ट कट में इसी तरह करना पड़ता है। पूरी बातचीत के दौरान उन्हें गल्ती का कोई अहसास हो इसके कोई संकेत नहीं थे। एक बार कलेक्टर के कहने पर वे ही अफसर मुझे एक मीटिंग में ले गये जिसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव आये थे। उस मीटिंग में उनका जो व्यवहार और तरीका था, वह मामला भी उन्हें नौकरी से निकालने और सजा देने के लिए पर्याप्त था। योगेन्द्र यादव द्वारा प्रकाशित पत्रिका सामयिक वार्ता में वह घटना छपी तो उन्होंने मुझे प्रणाम करते हुए आभार माना कि आपने मेहरबानी की, कि जिले का और मेरा नाम नहीं लिखा। उन्हें केवल यह चिंता रहती थी कि इस तरह की कहानियां मैं भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी शिकायत करते हुए तो नहीं बताता? ये घटनायें तो हांडी का चावल भी नहीं हैं। यह हाल तो उस जिले का था जहां के कलेक्टर पंचायत राज के काम के श्रेष्ठ अफसर माने जाते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री , मुख्य सचिव और संभाग आयुक्त की नजरों में अच्छा काम कर रहे थे। प्रदेश के अन्य जिलों में हालात इससे बेहतर तो नहीं ही थे।

2001 से 2004 तक मैं और तीन प्रध्यापक चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय की ओर से पूर्णकालिक कर्मचारी केवल पंचायतराज और ग्राम स्वाराज का काम जुनून की तरह कर रहे थे। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार के मार्गदर्शन में काम करने के साथ साथ मुख्यमंत्री के निकट होने के लिए भी कुख्यात था। बंद मुटठी लाख की जानता था इसलिए मैंने भी चुप्पी साध रखी थी ,जिसके कारण मुझे प्रदेश की नौकरशाही का उलेखनीय सहयोग मिलता रहा,अनुभव की कमी के कारण मैं उस सहयोग को अपनी सफलता मानता रहा। इस विशेष स्थिति में होने के बावजूद भी विकेन्द्रीयकृत स्वशासन की संस्थाओं ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को कानून की भावना के अनुसार काम करने के लायक नहीं बना सका। यद्यपि कुछ सकारात्मक काम भी हुए जिनका जरुरत से ज्यादा प्रचार हुआ जो दिमाग खराब करने के साथ साथ वास्तविकता समझने में बाधक हुए।

इन अनुभवों के बावजूद भी ये दिल है कि मानता नहीं, मन में पूरा है विश्वास कि जो हम नहीं कर सके वह अधिक समझदार,उर्जावान और प्रतिबद्ध साथी कर दिखायेंगे। वह सुबह कभी तो आयेगी।

क्या है ओल्ड मंक, जनरल डायर और देवभूमि का रिश्ता...!

परतें

संजीव शर्मा

आजादी की लड़ाई की सबसे निर्मम घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार क्रूर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर का देवभूमि हिमाचल प्रदेश से क्या संबंध है? इसी तरह, भारत सहित दुनिया भर में मशहूर रम 'ओल्ड मंक' का देवभूमि से क्या रिश्ता है? और इस सबसे जरूरी सवाल कि जनरल डायर,ओल्ड मंक एवं हिमाचल प्रदेश आपस में कैसे जुड़े हैं?

सबसे पहले बात ओल्ड मंक की। रम का पर्याय यह ब्रांड अपनी विरासत, विशिष्ट स्वाद और कम हैंगओवर के लिए भारत ही नहीं दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में लोकप्रिय है। वर्ष 2024-25 में ओल्ड मंक ने लगभग 1.3 करोड़ पेटी की बिक्री की जो प्रतिद्वंद्वी ब्रांड से बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यह बात कम लोग ही जानते होंगे कि 'बूढ़े साधु' यानि ओल्ड मंक का जन्म देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आज करीब 70 साल बाद भी यह डार्क रम सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी की कुल बिक्री का 80 फ़ीसदी हिस्सा इसी ब्रांड से आता है।

अब रही जनरल डायर के हिमाचल कनेक्शन की बात तो ओल्ड मंक ब्रांड ने जिस डिस्टिलरी या ब्रुअरी में जन्म लिया है,उसकी स्थापना जनरल डायर के पिता ने ही की थी और यह ब्रूअरी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। इसतरह खूंखार एवं निर्मम जनरल डायर के पिता द्वारा देवभूमि में स्थापित ब्रुअरी में दुनिया के इस मशहूर रम ब्रांड ने जन्म लिया और अपनी जन्मदाता कंपनी की कमाई को कई गुना बढ़ा दिया।

लेकिन, इसके पीछे की कहानी इतनी सरल नहीं है। इसमें सालों की मेहनत, रिसर्च, सोच और पीढ़ीगत बदलाव की अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं कि अब ओल्ड मंक किसी परिचय की मोहताज नहीं है लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत में भी कंपनी को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे भी मजेदार बात यह है कि इस लोकप्रिय ब्रांड के पीछे एक ऐसी विरासत है जो स्क्रैप और खाली बोतलों की सप्लाई से लेकर भारत के सबसे बड़े शराब कारोबारी बनने तक के सफर की कहानी है।

जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश फौज को सस्ती बीयर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1855 में एडवर्ड डायर ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में एशिया की सबसे पहली ब्रूअरी स्थापित की। इसको 'डायर ब्रुअरी' नाम दिया गया। यहां एशिया की सबसे पहली बीयर 'लॉयन' बनाई जाती थी। यह बीयर इतनी पसंद की गई कि यह धीरे धीरे उस दौर की शाही दावतों का हिस्सा बन गई।

'लॉयन' की सफलता से उत्साहित 'डायर ब्रुअरी' ने कसौली के करीब एवं हिमाचल प्रदेश के ही सोलन में 1920 में शराब बनाने के लिए दूसरा कारखाना स्थापित किया। यह ब्रुअरी ब्रिटिश उद्योगपति एच जी मीकिन के साथ साझेदारी में स्थापित की गई थी इसलिए इसका नाम डायर मीकिन ब्रुअरी रखा गया। इन दोनों शराब कारखानों के संस्थापक एडवर्ड अब्राहम डायर थे जो जनरल डायर के नाम से कुख्यात ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के पिता थे।

दरअसल, इस इलाके का पानी और उसका स्वाद कुछ खास है और शराब उत्पादन के लिए बहुमूल्य भी। अंग्रेज व्यवसायियों डायर और मीकिन को भी शायद यह जानकारी थी इसलिए उन्होंने इस जिले को बीयर एवं शराब बनाने के चुना। बताया जाता है कि यह पानी करोल पर्वत से बहकर नीचे को आता है। करोल पर्वत को करोल टिब्बा भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 7,349 फीट है। उधर, जब देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने जोर पकड़ा तो आजादी की लड़ाई का असर मौजूदा हिमाचल प्रदेश में भी दिखने लगा इसलिए अंग्रेजों की रुचि इन कारखानों में घटने लगी और 1947 में भारत के स्वतंत्र होते ही डायर और मीकिन के परिजनों ने कसौली तथा सोलन के कारखानों से पल्ला झाड़ लिया। उस दौर में एक भारतीय व्यवसायी नरेंद्र नाथ मोहन भी थे जो स्क्रैप और खाली बोतलों का व्यापार करते थे। करोल पर्वत के पानी की खासियत नरेंद्र नाथ मोहन भी बखूबी जानते थे और वे भी शराब कारोबार में उतरना चाहते थे।

इसलिए, जब नरेंद्र नाथ मोहन को पता चला कि अंग्रेज इन शराब कारखानों को बेचना चाहते हैं तो उन्होंने खरीदने में ज़रा भी देर नहीं की। देश के स्वतंत्र होते ही, दो साल के भीतर 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन ने अंग्रेजों से डायर मीकिन ब्रूअरी खरीद ली। 1966 में इसका नाम बदलकर मोहन मीकिन लिमिटेड कर दिया गया। मोहन मीकिन आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फुटबॉल की इसी नाम की टीम बहुत मशहूर रही है। कंपनी का कारोबार अब केवल शराब तक सीमित नहीं है। यह फलों के जूस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और मिनरल वाटर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी सक्रिय है।

नरेंद्र नाथ मोहन के निधन के बाद उनके बेटे कर्नल वेद रतन मोहन ने कंपनी को आधुनिक रूप दिया। 1950 के दशक में उन्होंने नई दिल्ली और गाजियाबाद में नई यूनिटें शुरू की और इसी दौर में 'ओल्ड मंक' का जन्म हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे 19 दिसंबर 1954 को लॉन्च किया गया था। बताया जाता है कि वेद रतन मोहन ब्लैक मॉन्क्स (बेनेडिक्टिन मॉन्क्स) की सादगी और अनुशासन से बहुत प्रभावित थे इसलिए उन्होंने रम के अपने नए ब्रांड का नाम 'ओल्ड मंक' रखा। ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम उन भिक्षुओं से प्रेरित है, जो अपनीगुफाओं में शराब को लंबे समय तक सहेज कर रखते थे।

वेद रतन मोहन के निधन के बाद उनके भाई ब्रिगेडियर कपिल मोहन ने कंपनी कीकमान संभाली। वे प्रादेशिक सेना में ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर कपिल मोहन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने 'ओल्ड मंक' का कभी विज्ञापन नहीं किया। उनका मानना था कि उत्पाद की गुणवत्ता ही उसका सबसे बड़ा विज्ञापन है। ब्रिगेडियर कपिल मोहन ने लगभग 40 वर्षों तक कंपनी का नेतृत्व किया और इसे वैश्विक पहचान दिलाई।

हालांकि 'ओल्ड मंक' को उनके भाई वेद रतन मोहन ने लॉन्च किया था, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने का श्रेय ब्रिगेडियर कपिल मोहन को जाता है। उनके नेतृत्व में यह दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली रम बनी। मजेदार तथ्य यह भी है कि पूरी दुनिया को रम पिलाने वाले कपिल मोहन खुद चाय प्रेमी थे। उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। वे समाज सेवा में भी काफी सक्रिय रहे और सोलन में बना अनूठा मोहन मीकिन विरासतपार्क कपिल मोहन की ही कल्पना का प्रतिबिंब है।

पंच परमेश्वर थे, अब ठेकेदार हो गए

पंचायत राज दिवस

डॉ. परशुराम तिवारी

पंचायत राज के शोधार्थी एवं प्रशिक्षक

भारत में वर्तमान पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसे 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य सत्ता काविकेंद्रीकरण और ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त बनाना भी था।

हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था में गाँव या कबीले के लोग मिलकर अनुभवी एवं समझदार व्यक्तियों की पंचायत लगाकर अपने आंतरिक विवादों का समाधान करते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बाद भी इस परंपरा के कुछ अवशेष आज भी दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इन पंचायतों के निर्णय इस भावना से प्रेरित होते थे कि सदस्य समदर्शी दृष्टि से विचार करें, उनका मन, वचन और निश्चय एक समान हो, जिससे समाज में समरसता और सुख-शांति बनी रहे।

इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध कहानी 'पंच परमेश्वर' में पंचों को न्याय और धर्म का प्रतीक माना और उन्हें परमेश्वर की उपमा दी। आजादी के बाद कई उतार-चढ़ावों के पश्चात 33 वर्ष पूर्व 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य था–ग्राम स्तर पर सुशासन स्थापित करना, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना तथा समग्र विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना।

किन्तु इन 33 वर्षों में यह व्यवस्था अपनी मूल भावना से भटकती हुई प्रतीत होती है। अपेक्षा थी कि गैर-दलीय जनप्रतिनिधि–पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य– विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे और लोकतंत्र की स्वच्छ नर्सरी बनेंगे, जो आगे चलकर विधानसभाओं और संसद को सशक्त एवं ईमानदार नेतृत्व देंगे।

परंतु आज स्थिति इसके विपरीत दिखती है। पंचायत प्रतिनिधि केवल भ्रष्टविधायक, सांसद और मंत्रियों को अपना आदर्श मानते हैं। यही कारण है कि अधिकांश पंचायतें राजनीतिक, सामाजिक दुश्मनी और आर्थिक अनियमितताओं के अड्डे बन कर रह गयी हैं। क्या है पंचायत राज व्यवस्था? भारत में पंचायत राज व्यवस्था जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है- निचले (ग्राम) स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर (ब्लॉक) पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला परिषद। इस व्यवस्था की विशेषता है कि सभी स्तरों पर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति सहित कमजोर वर्गों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

इस व्यवस्था की विशेषता है कि सभी स्तरों पर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति सहित कमजोर वर्गों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इन पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राज्य स्तर पर पंचायत राज संचालनालय, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं तथा वित्त आयोगों के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। कुल मिलाकर, व्यवस्थाओं और संसाधनों की दृष्टि से पंचायतों में कोई विशेष कमी नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था की प्रमुख खामियाँ ग्राम विकास, खुशहाली और आत्मनिर्भरता के लिए कुशल जनशक्ति का निर्माण अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य सौंपे गए थे–जैसे कृषि विस्तार, भूमि सुधार, जल प्रबंधन, लघु एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक वानिकी, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता आदि।

किन्तु विशेषकर मप्र के सन्दर्भ में जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक है। ग्राम भ्रमण और प्रशिक्षण के दौरान बार-बार यह अनुभव हुआ कि अधिकांश पुरुष पंच या सरपंच को इन 29 विषयों में से मुश्किल से 5-10 विषयों की ही जानकारी होती है, और वे विषय भी प्रायः ठेकेदारी से जुड़े होते हैं। महिला प्रतिनिधियों की स्थिति इससे भी अधिक दयनीय है। वे न तो पर्याप्त रूप से बैठकों में भाग ले पाती हैं और न ही निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाती हैं। कई स्थानों पर उनकी भूमिका केवल निर्णयों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित होती है। असल में निर्णय उनके पति या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। एक तथ्य यह भी है कि पंचायत व्यवस्था का पर अब तीन ताकतों का नियंत्रण हो गया है- सरपंच या शक्तिशली व्यक्ति, पंचायत सचिव और सीईओ है। जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सत्ता दल के ऊपरी राजनीतिक नेतृत्व का हस्तक्षेप है। इस तरह पंचायत व्यवस्था में अब 'पंच परमेश्वर' की भावना लगभग समाप्त हो चुकी है। पंचायत प्रतिनिधियों का ध्यान ग्राम स्वराज या समग्र विकास के बजाय ठेकेदारी और आर्थिक लाभ तक सीमित होता जा रहा है।

क्या सुधार आवश्यक हैं?

विगत 33 वर्ष में अरबों रूपये खर्च करके भी भारत सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अब तक मप्र में राज्य की लगभग 23 हजार में से एक भी आदर्श ग्राम पंचायत या सांसद ग्राम नहीं बना सकी है। आत्मनिर्भर और खुशहाल पंचायत की तो चर्चा ही व्यर्थ है। यदि पंचायत राज व्यवस्था वापस पटरी पर लाना है तो सरकार और नागरिक समाज को फिर से ईमानदार प्रयास करना होंगे। इस हेतु कुछ सुधार तत्काल आवश्यक हैं जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों का उचित प्रक्रिया से वर्षिक आधार पर प्रशिक्षण सपोर्ट एवं निगरानी में दक्ष स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी और जिम्मेदारी तय होना, महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पृथक से प्रशिक्षण आयोजित करना, सचिव और सीईओ के गठजोड़ की सर्जरी, प्रशासनिक नियत्रण कम करना, कामकाज में राजनीतिक दखल की समाप्ति, पंचायतों के स्वयं के राजस्व के स्रोत बढ़ाना, केंद्र और राज्य स्तर से समय पर बजट/ अनुदान राशि का आवंटन, सभी कार्यों में ग्राम सभा के उचित आयोजन द्वारा सामुदायिक सहभागिता पारदर्शिता बढ़ाना, नवाचारों द्वारा मानव विकास सूचकांकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना आदि विशेष रूप से शामिल हैं। आज आवश्यकता है कि सरकार और नागरिक समाज मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें, ताकि पंचायतें पुनः 'पंच परमेश्वर' की भावना के साथ कार्य कर सकें और ग्रामीण भारत के सशक्त, आत्मनिर्भर और समरस विकास का आधार बन सकें।

जनगणना 2027: भीमपुर क्षेत्र में स्व-गणना अभियान को मिला जनसमर्थन

बैतूल। भीमपुर में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में गुरुवार को स्थानीय नागरिकों के बीच जाकर जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना करने और जनगणना में उत्साह से भागीदारी करने की अपील की गई।

अनुविभागीय जनगणना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैंसदेही श्री अजीत मरावी, जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम, तहसीलदार एवं अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी भीमपुर श्री बसंत बरखानिया तथा स्व-गणना पोर्टल के तकनीकी सहायक श्री विवेक दायमा द्वारा आमजनों को तकनीक की सहजता और जनगणना का महत्व बताते हुए, स्व की गणना की अपील की गई। अधिकारियों द्वारा मौके पर ही ग्रामीणों को स्व-गणना पोर्टल की जानकारी दी गई और उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए स्वयं की उपस्थिति में स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। इससे ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई।

उत्सुक ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए बताया कि स्व-गणना के माध्यम से समय की बचत होती है तथा प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनती है। स्व-गणना डिजीटल अभिनव पहल से क्षेत्र में जनगणना कार्य को गति मिलने के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इसी प्रकार के प्रयासों से जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकेगा।

प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का अंतिम सत्र प्रशिक्षण शुरू

बैतूल। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को प्रभावी, सटीक एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का फील्ड प्रशिक्षण अभियान सुदृढ़ रूप से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के नेतृत्व तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट के मार्गदर्शन में नगरीय एवं ग्रामीण चार्ज मुख्यालयों पर आयोजित यह प्रशिक्षण फील्ड स्तर पर कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 17 अप्रैल 2026 तक जिले की 9 तहसीलों के ग्रामीण चार्जों में 733 प्रगणक एवं 124 पर्यवेक्षक तथा 19 से 21 अप्रैल 2026 तक द्वितीय सत्र में 26 बैच के माध्यम से 10 ग्रामीण एवं 4 नगरीय चार्जों के कुल 937 प्रगणक एवं 159 पर्यवेक्षक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। इसी क्रम में तृतीय एवं अंतिम सत्र में 30 बैच अंतर्गत 19 चार्ज में लगभग 1040 प्रगणक एवं 190 पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण 22 से 25 अप्रैल अंतर्गत 30 बैचों के माध्यम से 10 ग्रामीण चार्ज-तहसील आमला, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, घोड़ाडोंगरी, प्रभात पट्टन, मुलताई, शाहपुर, चिचोली एवं आठनेर में लगभग 730 प्रगणकों एवं 130 पर्यवेक्षकों एवं 09 नगरीय चार्ज क्रमश : बैतूल, आमला, मुलताई, सारनी नगर पालिका और आठनेर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, शाहपुर एवं भैंसदेही नगर परिषद के लगभग 310 प्रगणकों और 60 पर्यवेक्षकों को 64 फील्ड ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जनगणना की मूल अवधारणा से ऐप आधारित प्रशिक्षण : प्रथम दिवस में प्रतिभागियों को जनगणना की मूल अवधारणा, महत्व, विधिक प्रावधान, डेटा गोपनीयता एवं सटीकता संबंधी निर्देशों के साथ-साथ प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका एवं दायित्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एचएलओ मोबाइल एप के उपयोग, तकनीकी विशेषताओं, डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया एवं फील्ड में इसके प्रभावी संचालन पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को व्यावहारिक दक्षता प्रदान करने हेतु हैंड्स-ऑन सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

निरंतर मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता पर विशेष फोकस : कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय जनगणना अधिकारियों द्वारा अपने-अपने अनुभागों में प्रशिक्षण की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही गुरुवार को जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी नरेन्द्र कुमार गौतम द्वारा बैतूल, भीमपुर प्रशिक्षण सत्रों का निरीक्षण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई।

नल-जल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए पंप चालकों को दिया प्रशिक्षण

बैतूल। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल जीवन मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नल-जल योजनाओं के बेहतर संचालन एवं संधारण को लेकर गुरुवार को विकासखंड आमला में विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड बैतूल के निर्देशन एवं जनपद पंचायत आमला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समन्वय से आयोजित इस प्रशिक्षण में 55 ग्रामों के पंप चालकों को योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में ट्यूबवेल मोटर पंप, उच्चस्तरीय जल टंकी, सम्पवेल, पाइपलाइन, पंप हाउस, वाल्व चैंबर, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन जैसे महत्वपूर्ण अवयवों की देखरेख, सुधार एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही प्रतिदिन, मासिक, छमाही एवं वार्षिक आधार पर किए जाने वाले रखरखाव कार्यों पर विशेष जोर दिया गया।पंप चालकों को मोटर संचालन के घंटे, जल आपूर्ति की अवधि, विद्युत खपत, पाइप लाइन लीकेज एवं टूट-फूट जैसी जानकारियों का नियमित रिकॉर्ड रखने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा टंकी, सम्पवेल एवं वाल्व चैंबर की नियमित सफाई कर तिथि दर्ज करने तथा लीकेज की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल स्त्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, वर्ष में कम से कम दो बार प्रयोगशाला में जल परीक्षण कराने तथा पंचायत स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से प्रतिमाह जल नमूनों की जांच कराने के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान जल संरक्षण, पेयजल के अपव्य को रोकने एवं जल स्त्रोतों के रिचार्ज की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई। साथ ही योजनाओं से अधिकतम जलकर प्राप्त करने के उपाय भी बताए गए। उक्त प्रशिक्षण जिला समन्वयक श्री भूपेंद्र सिंह मेनवे, उपयंत्री श्री तौफीक शाह, विकासखंड समन्वयक श्रीमती आभा तिवारी एवं हैंडपंप तकनीशियन श्री गोपाल मसोदकर द्वारा प्रदान किया गया।

लाव -लश्कर के साथ थाने पहुंचे विधायक

सोहागपुर। सोहागपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का संचालन होने क्षुब्ध होकर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह लाव लश्कर के साथ थाने पहुंचे। यहां एसडीओ पुलिस संजू चौहान एवं नगर निरीक्षक राहुल रायकवार को कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा है। जिसमें सट्टा, जुआं एवं अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने की बात कही है। उन्होंने आगाह किया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का संचालन बढ़ रहा है। इससे आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। आपने पुलिस विभाग को चेताया कि सट्टा जुआं अवैध शराब बिक्री एवं रेत का अवैध कार्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारियों ने विधायक विजयपालसिंह को आश्वस्त किया है कि 5 दिनों में सब पर अंकुश लगा दिया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों भारी संख्या में उपस्थित थे।

किसानों को बाजार दर का चार गुना मुआवजा मिलेगा : डॉ. योगेश पंडाग्रे

मंत्री परिषद द्वारा किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय पर बोले प्रदेश प्रवक्ता

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे ने जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित प्रेस ब्रिफिग के दौरान कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में किसानो के हित में लिए गए बडे फैसलो का हम स्वागत करते है। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। अब कृषि भूमि के भू अर्जन पर किसानो को बाजार दर का चार गुना मुआवजा मिलेगा जो प्रदेश के विकास को रफतार देगा। श्री पंडाग्रे ने इस निर्णय को एतिहासिक बताते हुए कहा कि यह फैसला किसानो के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ प्रदेश के विकास को गति देने वाला है। पिछले तीन वर्षो में 55 हजार से अधिक किसानो को तकरीबन 16 हजार करोड का मुआवजा दिया गया। जिसे बढाकर हर साल करीब 20 हजार करोड रू. किया जाएगा। श्री पंडाग्रे ने पत्रकारो से चर्चा करते हुए कहा कि बडे हुए मुआवजे से सिंचाई परियोजनाएं, सडक ,पूल और रेल्वे जैसे विकास कार्यो में तेजी आएगी। प्रदेश सरकार ने अधोसंरचना विकास के लिए 33,985 करोड रू. की स्वीकृति भी दी हैं जिससे किसानो को सिंचाई सहित बुनियादी सुविधाओ का लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री पंडाग्रे ने कहा कि विपक्ष का दायित्व किसानो के सशक्तिरण से जुडे ऐतिहासिक फैसलो का स्वागत करना होना चाहिए। वहीं विपक्ष अनावश्यक राजनीति करने से बाज नही आ रहा है। कृषि भूमि के भूअर्जन पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने वाला कदम किसनो की आय सम्मान और भविष्य से जुडा है। इसके बावजुद विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। जो स्पष्ट करता है कि विपक्ष की प्राथमिकता किसानो का हित नही बल्कि राजनीतिक लाभ है। श्री पंडाग्रे ने पत्रकारो के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह निर्णय किसानो को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। प्रदेश में अधोसंचरना विकास को भी नई गति देगा जिससे रोजगार के अवसर बढेगें। चार गुना मुआवजे की प्रेस ब्रिफिंग के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री अशोक पानसे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष महेश्वर सिंह चंदेल, जिला मीडिया प्रभारी सूर्यदीप त्रिवेदी विशेष रूप से मौजूद रहे।

ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले आरोपी इंदौर से गिरफ्तार

बैतूल। थाना कोतवाली बैतूल ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त कर दो आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस मामले में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा विवेचना करते हुए टीम रवाना कर बैतूल में पकड़ाई ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले भूपेंद्र उर्फ़ बॉबी पिता रामकृष्ण लोवंशी उम्र 26 साल निवासी 40/2 किंग्स पार्क न्यू गौरी नगर इंदौर थाना हीरानगर इंदौर और आशुतोष उर्फ आशु पिता देवेंद्र सिंह सिसोदिया उम्र 28 साल निवासी इंडस ग्रीन सैटेलाइट देवास नाका इंदौर थाना लसूडिया इंदौर को इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उक्त आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाही में निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उप निरीक्षक राकेश सरयाम, उप निरीक्षक छत्रपाल, प्रधान आरक्षक शिव उइके, आरक्षक अनुरुद्ध यादव, आरक्षक नितिन चौहान, आरक्षक दीपेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक निर्णय भू अर्जन पर किसानों को 4 गुना मुआवजा बढ़ाने के निर्णय पर भाजपाईयों ने आभार जताकर आतिशबाजी की

धार। प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार द्वारा मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए गुरुवार को मोहन टाकीज चौराहे पर भाजपा नगर एवं किसान मोर्चा द्वारा धार में किसान भाइयों एवं नागरिकों को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। इस अवसर पर किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रवि पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष जयराज देवड़ा, विशाल निगम समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अर्जन पर किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देने का यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। इससे न केवल किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार आएगा। साथ ही विकास कार्यों सड़क, सिंचाई, रेलवे एवं अन्य अधोसंरचना को भी गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के सशक्तिकरण का जो संकल्प लिया गया है, उसी दिशा में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए सभी किसान भाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर शरद विजयवर्गीय ,डॉ कमल जैन भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा,मनीष प्रधान, अंकित भावसार,टोनी ठाकुर, सन्नी होड़ा, कमलेश बिजवा, सोनू रघुवंशी, अनिल गहलोत ,कैलाश पिपलोदिया, रितेश अग्निहोत्री, नवदीप सिंह चौहान,राकेश वर्मा,देवेंद्र रावल बादल मालवीय, करण, नमन रावल पटेल हरीश आर्य दिनेश चौहान वीरेंद्र ठाकुर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भाजपा की प्रेस वार्ता

विपक्ष पर तीखा प्रहार, महिला विरोधी गठबंधन ने इस ऐतिहासिक अवसर को बाधित कर अपनी वास्तविक मानसिकता उजागर की

आज की नारी केवल मतदाता नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुकी है : केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर

धार। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' संशोधन प्रस्ताव के संसद में पारित नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला कार्यालय धार में गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री व धार -महू सांसद सावित्री ठाकुर ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती तथा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राखी राय, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुसुम सौलंकी, मोर्चा महामंत्री सुनिता दुबे उपस्थित रहे।

श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक देश की आधी आबादी के सम्मान,अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद में जो हुआ, वह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'महिला विरोधी गठबंधन' ने इस ऐतिहासिक अवसर को बाधित कर अपनी वास्तविक मानसिकता उजागर कर दी है। भाजपा सरकार ने महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का जो संकल्प लिया है, वह किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ेगा। भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, जन-धन खाते, मातृत्व सुरक्षा योजनाएं और तीन तलाक जैसे फैसलों ने महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी तक सीमित रहा है।

आज की नारी केवल मतदाता नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, वे भाजपा की नीतियों का परिणाम हैं।

श्रीमती ठाकुर ने कहा कि 2001 की जनगणना के बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यह निर्णय लिया गया कि 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन स्थगित रहेगा, ताकि दक्षिणी राज्यों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। इसके बावजूद विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस, डीएमके और उनके सहयोगियों के इस महिला-विरोधी गठबंधन ने न केवल एक विधेयक को रोका, बल्कि करोड़ों महिलाओं के अधिकारों और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और विडंबना देखिए-इस पर विपक्ष जश्न मनाता रहा। विपक्ष का जश्न, हर महिला का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में यह मुद्दा जन-जन तक जाएगा और महिलाएं स्वयं तय करेंगी कि उनके सशक्तिकरण के साथ कौन खड़ा है। प्रेस वार्ता में नेताओं ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुद्दा अब जन-आंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस घटनाक्रम को समझ रही हैं और भविष्य में इसका असर चुनावों में भी दिखाई देगा।

एसडीएम डॉ.अभिजीत सिंह ने छात्रावासों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से लिया फीडबैक

बैतूल । कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार 23 अप्रैल को अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल डॉ. अभिजीत सिंह द्वारा बैतूल मुख्यालय स्थित सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री सिंह ने छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं से संवाद कर भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया तथा आवासीय कक्षों का अवलोकन किया। साथ ही उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में छात्र-छात्राओं से फीडबैक प्राप्त किया गया। इस दौरान छात्रावास परिसर में स्नानागार एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत एसडीएम श्री सिंह ने आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए संबंधित छात्रावास अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए।

ग्वालियर से राशि भेजकर कराया भोजन

सोहागपुर। रेल्वे स्टेशन परिसर में जरूरतमंद नागरिकों एवं महिलाओं को निरंतर भोजन कराने वाली संस्था राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से सहयोग करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है।इसी तारतम्य में सोहागपुर विधानसभा के माखननगर बाबई निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डीके रैना की बहन ग्वालियर निवासी श्रीमती मंजू द्वारा अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती आशा रैना की पुण्यतिथि पर सहयोग राशि भेज कर राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से जरूरतमंद बेघर बेसहारा लोगों को भोजन कराया गया।।

सरकार का लक्ष्य है कि किसानों का एक-एक दाना खरीदेंगे,लगेंगे सीसीटीवी कैमरे : विधायक विजयपाल सिंह

सोहागपुर। प्रदेश भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों का अहित नहीं होगा। पूर्व में पांच एकड़ तक के किसानों का पंजीकरण हो रहा था। गुरूवार से उससे अधिक एकड़ वाले किसानों का पंजीकरण होगा। एवं उपज की खरीदी होगी। उक्त उद्गार क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहें। आपने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसानों के हित के हमेशा तत्पर है। इसी क्रम आपने कहा कि नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम दान दाताओं से सहयोग लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आने वाले दो महीनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने कार्य पूरा होने की संभावना है।इससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लग जाएगा। स्थानीय पत्रकारों ने नगर के ज्वलंत मुद्दों को विधायक विजयपालसिंह का ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में कदम उठाएं जाएं। जिससे नागरिकों को सुविधा उपलब्ध हो सके। आज दिन पलकमती नदी पुल के पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग पर जाम लग जाता है। वहीं सड़कों पर घूम रही गौ माताओं एवं गौशालाओं के संचालक पर चर्चा की गई । विधायक ने कहा कि गौशालाओं का संचालन स्व सहायता समूहों को दिया गया है ।यह स्व सहायता समूह गोबर से खाद बनाकर, गोबर से गौकास्ट बनाकर, गौ मूत्र से गौ आर्क का निर्माण कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा गौशालाओं में 20 रूपये प्रति पशु आहार के लिए दिए जाते थे । सरकार ने अब राशि बढ़ाकर रु 40 प्रति पशु कर दिया है। इस राशि से पशुओं की अच्छी तरह देखभाल हो सकती है । इसके साथ गौ शालाओं का संचालन अच्छे से किया जा सकता है। इस कार्य में समाज की भागीदारी भी आवश्यक है। अतिक्रमण के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम यातायात को सुलभ बनाएगी। आपने पत्रकार वार्ता में कहा कि सोहागपुर ब्लॉक में सट्टा जुआ एवं अवैध शराब का व्यापार बड़े स्तर हो रहा है। इस मामले में आज थाना में पहुंचकर पर अवांछनीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गतिविधियां संचालित हो रही है। इस कारण अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। इस कारण अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इस अवसर पर भाजपा कई भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

छात्राओं को कराया गया पशु आहार संयंत्र का शैक्षणिक भ्रमण

सीहोर,(निप्र)। सीहोर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रायोजित एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत पचामा स्थित सांची पशु आहार संयंत्र का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान छात्राओं को औद्योगिक प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों एवं उत्पादन प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. प्रमोद शर्मा एवं विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज जैन ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, व्यावहारिक ज्ञान एवं कौशल संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उन्हें भविष्य में रोजगारोन्मुख बनने में सहायता प्रदान करते हैं। भ्रमण के दौरान श्रीमती पूजा जारोलिया, श्रीमती शाजिया खान, श्री विश्वास बगवैया, श्री हेमंत अम्बलकर एवं श्री रविरंजन उपस्थित थे।

अपेक्स वेयर हाउस रूसल्लीसाहू लटेरी का निरीक्षण, गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया

विदिशा,(निप्र)। अपेक्स वेयरहाउस रूसल्लीसाहू, लटेरी में सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री रघुवंशी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस में संचालित गेहूं खरीदी कार्यों की व्यवस्थाओं का विस्तार से अवलोकन किया। इस अवसर पर सहकारिता विस्तार अधिकारी ने समूह की दीदी प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर से चर्चा करते हुए गेहूं खरीदी प्रक्रिया, किसानों के पंजीयन, तौल व्यवस्था, भुगतान प्रणाली एवं रिकॉर्ड संधारण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने खरीदी कार्य में पारदर्शिता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने की बात कही गई। साथ ही खरीदी केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने एवं समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

नर्मदापुरम में छात्रों के प्रोजेक्ट से आएगा सामाजिक बदलाव: डॉ. बकुल लाड

नर्मदापुरम,(निप्र)। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत मास्टर ऑफ सोशल वर्क और बैचलर ऑफ सोशल वर्क के छात्र अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की नींव रख रहे हैं। यह बात मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड ने पी एम श्री कॉलेज नर्मदापुरम के निरीक्षण के दौरान कही। निरीक्षण के दौरान डॉ. लाड ने छात्रों की प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जब ज्ञान जमीन पर उतरता है तभी समाज की तस्वीर बदलती है। डॉ. लाड ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मकसद ऐसे सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तैयार करना है जो शासन और समाज के बीच सेतु बनें। उन्होंने छात्रों को प्रोजेक्ट्स के सुझावों को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया। डॉ. लाड ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, 'आप केवल डिग्री हासिल नहीं कर रहे, बल्कि समाज के सच्चे बदलाव कर्ता बन रहे हैं। आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स एक विकसित और जागरूक समाज का खाका हैं।' उन्होंने विविध कार्यों में सक्रिय भागीदारी को स्थायी बदलाव की कुंजी बताया।निरीक्षण के दौरान संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी, ब्लॉक समन्वयक नरेंद्र देशमुख, मेंटर्स नीरज चतुर्वेदी, राजेंद्र कुशवाह, अभिषेक सैनी, विनीत यादव और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 5996 बालिकाओं का किया टीकाकरण

हरदा,(निप्र)। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बुधवार 22 अप्रैल तक जिले में कुल 5996 बालिकाओं को टीकाकरण किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने बताया कि हरदा में 1042, टिमरनी में 1188, खिरकिया में 1162, सिराली में 527, रहटगांव में 600, हंडिया में 1477 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार जिले में कुल 6715 के लक्ष्य विरूद्ध 5996 कुल 89.29 प्रतिशत बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण किया गया। डॉ. सिंह ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी से होता है। एचपीवी टीका एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो कैंसर से बचाने में मदद करता है। यह टीका जिला चिकित्सालय हरदा तथा टिमरनी, सिराली, खिरकिया व हंडिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा रहटगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नि:शुल्क लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि ऐसी बालिकाएं जिनकी आयु 14 वर्ष तथा 15 वर्ष 3 माह तक की है वे अपनी बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाएं।

कलेक्टर की पहल से जनसुनवाई में दिखा नवाचार

नर्मदापुरम,(निप्र)। आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय का दृश्य कुछ अलग ही नजर आया। जनसुनवाई कक्ष में एक ओर जहां जिला स्तरीय अधिकारी एक पंक्ति में बैठकर आवेदकों की समस्याओं के निराकरण में जुटे थे, वहीं मध्य में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ आवेदकों को अपने समक्ष बैठाकर उनकी समस्याएं सुनते हुए दिखाई दिए। जनसुनवाई के दौरान दूसरी पंक्ति में सभी आवेदक अपनी-अपनी बारी के अनुसार बैठे थे। आवेदकों ने क्रमवार अपनी समस्याएं कलेक्टर श्री मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु जैन एवं अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए यथा संभव मौके पर ही समाधान किया।

भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा एक नवाचार भी किया गया। उन्होंने जनसुनवाई कक्ष में ही आवेदकों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई तथा सभी को शरबत पिलवाया, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी आवेदक खड़ा न रहे और सभी को क्रमवार बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएं।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने अपने समक्ष कुर्सी लगवाकर सीधे आवेदकों से संवाद किया और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया। इस

दौरान कुल 121 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर श्री मिश्रा के निर्देशानुसार 21 अप्रैल से जनसुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए इसे ग्राम पंचायत स्तर तक प्रारंभ किया गया है। अब ग्रामीण नागरिक अपनी समस्याएं नजदीकी ग्राम पंचायत में ही संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे, जिससे उन्हें जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने विभिन्न आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान माखन नगर तहसील के कृषक श्री अनिल कुमार दुबे ने सीमांकन प्रकरण की नकल उपलब्ध न कराए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। इस पर कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसीलदार माखन नगर को निर्देशित किया कि दो दिवस के भीतर सीमांकन प्रकरण की नकल तैयार कर संबंधित को उपलब्ध कराई जाए।

इसी प्रकार सोहागपुर निवासी श्री अमित दीक्षित ने ग्राम डूडादेह स्थित अपनी कृषि भूमि के सीमांकन में विलंब की समस्या रखी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर तिथि निर्धारित होने के बावजूद सीमांकन नहीं हुआ है। कलेक्टर ने एसडीएम सोहागपुर को निर्देश दिए कि सात दिवस के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माखन नगर निवासी श्रीमती किरण पवार द्वारा कृषि भूमि के बंटवारे संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम नर्मदापुरम को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इटारसी तहसील के श्री केसरी सिंह के भू-अभिलेख सुधार के आवेदन पर कलेक्टर ने तहसीलदार इटारसी को सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम काजलखेड़ी के श्री संतोष कुमार के अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरण में तहसीलदार माखन नगर को एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। नर्मदापुरम निवासी श्री कमलेश कुमार द्वारा अवैध कब्जा हटाने, सड़क निर्माण एवं साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर ने सीएमओ नर्मदापुरम को एक सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन, एडीएम श्री अनिल जैन, अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत, सिटी मजिस्ट्रेट श्री देवेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सरोज परिहार एवं श्रीमती नीता कोरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही जारी

नर्मदापुरम,(निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्पूर्ण जिले में कार्यवाही जारी है। खनिज, राजस्व विभाग एवं पुलिस थाना माखननगर द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम-आँचलखेड़ा तवा पुल, तहसील-माखननगर में 03 डम्पर क्रमशः क्र मां क - RJ17GA9624, MP04HE8411 एवं MP04ZG 0883 को रेत खनिज का ओवरलोड परिवहन करते जप्त कर पुलिस थाना माखननगर की अभिरक्षा में रखा गया है।

कार्यवाही में श्री दिवेश मरकाम, जिला खनि अधिकारी, श्री सुनील गढेवाल, तहसीलदार माखननगर, श्री कृष्णकांत सिंह परस्ते, प्र0 खनि निरीक्षक, श्री हेमन्त राज सिपाही खनिज, पुलिस एवं होमगार्ड बल उपस्थित रहा। उक्त जप्त वाहनों के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

महिला स्व-सहायता समूह ने संभाली उपार्जन केन्द्र की कमान, सुव्यवस्थित संचालन बना मिसाल

विदिशा,(निप्र)। ग्यारसपुर तहसील के ग्राम सियासी स्थित उपार्जन केन्द्र पर इस वर्ष महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किए जा रहे सुव्यवस्थित संचालन ने एक नई मिसाल पेश की है। समूह की महिलाओं ने जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करते हुए केन्द्र पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल रही है। उपार्जन केन्द्र पर तौल, पंजीयन, भंडारण एवं परिवहन जैसी व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से संचालित किया जा रहा है। महिला समूह की सक्रियता के चलते किसानों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ रहा है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रही है। समूह की सदस्याएं प्रतिदिन समय पर उपस्थित होकर कार्यों का विभाजन करती हैं और आपसी समन्वय से सभी व्यवस्थाएं संभालती हैं। केन्द्र पर साफ-सफाई, दस्तावेजों का संधारण एवं किसानों से संवाद भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जिससे किसानों में संतोष का माहौल है। स्थानीय किसानों ने महिला स्व-सहायता समूह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पहले जहां अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थीं, वहीं अब कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी से न केवल व्यवस्थाएं सुधरी हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। महिला समूह के इस प्रयास की सराहना की जा रही है और इसे अन्य उपार्जन केन्द्रों के लिए प्रेरणास्रोत बताया जा रहा है। यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो रही है।

लंबित निर्माण कार्यों पर सख्ती, पेयजल समस्या का 7 दिन में समाधान सुनिश्चित करें - कलेक्टर डॉ सोनवणे

बैतूल,(निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने जनपद पंचायत मुलताई के सभाकक्ष में बैठक लेकर मुलताई एवं प्रभातपट्टन विकासखंड में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायतों में कोई भी स्वीकृत कार्य लंबित न रहे और विभिन्न मदों के माध्यम से सभी कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने पेयजल समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देशित किया कि चिन्हित सभी प्रभावित ग्रामों में 7 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से बोरिंग कराई जाए, ताकि भविष्य में दोबारा संकट उत्पन्न न हो। साथ ही जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने पर जोर देते हुए रिचार्ज वेल, डगवेल और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों को पूर्ण कर संबंधित पोर्टल पर प्रविष्टि करने के निर्देश दिए।

पीएचई विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी नल-जल योजना बंद न रहे। मरम्मत, पाइपलाइन एवं बोरिंग कार्यों को प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही एपीओ मनरेगा को अधिक से अधिक जल संरक्षण कार्य लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 15वें वित्त आयोग की राशि के सुव्यवस्थित उपयोग और पंचायतों की आय बढ़ाने के प्रयास करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से पंचायतों में रूफटॉप सोलर पैनल परियोजनाएं शुरू करने पर जोर दिया।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने सख्त चेतावनी दी कि जिन ग्रामों में पेयजल समस्या बनी रहेगी, वहां संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हैंडपंप और बोरिंग कार्यों में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति में किसी प्रकार की देरी न हो, यह भी सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने शिक्षा विभाग एवं पंचायतों को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में शौचालय एवं छत की स्थिति बेहतर रहे। जहां समस्या है, वहां तत्काल मरम्मत कार्य कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जर्जर स्कूल भवन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियरों को समस्याग्रस्त स्कूलों की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनभागीदारी से डेस्क-बेंच की व्यवस्था एवं स्कूलों का वातावरण आकर्षक बनाने पर बल दिया।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने कृषि विभाग को किसानों के पंजीयन से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। संबल योजना की समीक्षा करते हुए लेबर इंस्पेक्टर की ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रभातपट्टन में प्रगति बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। कम प्रगति पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रभात पट्टन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दोनों जनपदों में अभियान चलाकर पूर्ण निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कर सीसी जारी करने को कहा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा महतो, जनपद सीईओ मुलताई एवं प्रभातपट्टन, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पी.एम.श्री विद्यालयों में उत्साहपूर्वक मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस

विद्यार्थियों ने लिया हरित पृथ्वी का संकल्प

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में बुधवार को जिले के समस्त पीएम श्री विद्यालयों में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन के प्रति जागरूकता विकसित करना रहा। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण विषय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को जल, जंगल और जमीन के महत्व से अवगत कराया गया।

इसके साथ ही निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कर विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रमों के अंतर्गत 'बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट' प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें विद्यार्थियों ने प्लास्टिक की बोतलों, पुराने समाचार पत्रों एवं अन्य अपशिष्ट सामग्रियों का उपयोग कर उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) का महत्व समझाया गया। इसके अलावा विद्यालय परिसरों में वृक्षारोपण किया गया तथा पौधों की सुरक्षा और देखभाल के बारे में जानकारी दी गई। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को 'स्वच्छ एवं हरित पृथ्वी' बनाने की शपथ भी दिलाई गई। आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पालकी, कुआं खेड़ी का किया निरीक्षण, योजनाओं की समीक्षा कर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज ग्राम पंचायत पालकी एवं कुआं खेड़ी का दौरा कर पंचायत में संधारित विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड संधारण की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने पंचायत स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

उन्होंने योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, विभिन्न मदों से कराए जा रहे निर्माण कार्यों, पेयजल आपूर्ति के प्रबंधों तथा महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल सके। इस दौरान कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के नामों की सूची दीवार लेखन के माध्यम से ग्राम में प्रदर्शित की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आमजन को योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ विकास कार्यों को गति दी जाए, जिससे ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण, पोषण एवं टीकाकरण सेवाओं की ली जानकारी

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बुधवार को भ्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां प्रदाय की जा रही सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम कुआं खेड़ी एवं पालकी स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें मिल रही पोषण सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विशेष रूप से पोषण मटका के संधारण के उद्देश्य के बारे में जानकारी लेते हुए संबंधित कार्यकर्ताओं को इसे नियमित रूप से अद्यतन रखने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों के पोषण स्तर की सतत निगरानी सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उनके उपचारात्मक प्रबंधन की स्थिति की जानकारी ली। साथ

ही बच्चों के टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी पात्र बच्चों का समय पर पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के समग्र विकास की आधारशिला हैं, अतः यहां संचालित सभी गतिविधियों में गुणवत्ता एवं नियमितता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुपोषण मुक्त अभियान को प्राथमिकता के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए।

खेत तालाब का निर्माण: जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल

विदिशा,(निप्र)। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालकी के लाला खेड़ी गाँव में खेत तालाब निर्माण का कार्य किया गया है। यह कार्य वर्ष 2024-25 के तहत ग्राम पंचायत पालकी में संपन्न हुआ, जो क्षेत्र में जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कलेक्टर ने किया स्थल निरीक्षण - कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान उक्त खेत तालाब का मुआयना किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं जल संरक्षण के दृष्टिकोण से इसकी प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ

मिल सके। साथ ही उन्होंने जल संरक्षण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। कार्य का विवरण - इस परियोजना के अंतर्गत 'खेत तालाब निर्माण' कार्य को प्राथमिकता देते हुए किसानों के खेतों में जल संग्रहण की व्यवस्था विकसित की गई है।

तालाब के निर्माण से वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकेगा, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कार्य की कुल स्वीकृत राशि 3.32 लाख रुपये है, जिसके माध्यम से स्थानीय मजदूरों को रोजगार भी मिला। इस कार्य में कुल 261 मानव दिवस का सृजन हुआ, जो योजना के मुख्य उद्देश्य रोजगार की उपलब्धता को पूर्ण कर रहा है। प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग - यह कार्य ग्राम पंचायत पालकी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही।

निर्माण कार्य की निगरानी एवं क्रियान्वयन में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो सका। किसानों को मिलेगा लाभ - खेत तालाब निर्माण से किसानों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। सिंचाई के लिए वर्षभर पानी की उपलब्धता। फसल उत्पादन में वृद्धि। भूजल स्तर में सुधार। सूखे की स्थिति में राहत मिल रही है। मनरेगा के अंतर्गत किया गया यह खेत तालाब निर्माण कार्य जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा द्वारा किए गए निरीक्षण से कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ ही भविष्य में ऐसे और कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

धार भोजशाला मामला

एएसआई के निष्कर्ष अकेले भोजशाला का मालिकाना हक तय नहीं कर सकते

हाईकोर्ट में सलमान खुर्शीद की दलीलें

इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोजशाला परिसर को लेकर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पेश हुए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान मौजूदा याचिका और अयोध्या मुकदमे के बीच एक फर्क बताया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राम मंदिर मामले में, राम लल्ला विराजमान यानी देवता खुद याचिकाकर्ता थे। साथ ही मंदिर की देखभाल करने वाले शेबैत भी उनके साथ थे।

सिर्फ जमीन होने से कोई देवता नहीं बन जाता

सलमान खुर्शीद ने कहा कि भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद मामले में, ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर आज मस्जिद खड़ी है, उसी जमीन से किसी देवता का जुड़ाव है या उसी जमीन के संबंध में किसी देवता की कल्पना की गई है।

ये दिया तर्क- सुनवाई के दौरान उन्होंने दलील दी कि ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी किसी पवित्र उद्देश्य के लिए किए गए स्पष्ट समर्पण से पैदा होती है। उस उद्देश्य के कानूनी प्रतिनिधि के दौरान मूर्ति में समाहित होती है। उन्होंने कहा कि मूर्ति के न होने या नष्ट हो जाने पर भी वह उद्देश्य खुद बना रह सकता है लेकिन जमीन या इमारतें सिर्फ धार्मिक जुड़ाव की वजह से ऐसा कानूनी व्यक्तित्व हासिल नहीं कर लेतीं।

एएसआई के सबूतों पर उठाया सवाल- इसके साथ ही खुर्शीद ने एएसआई की खोजों को दिए जा रहे सबूतों के महत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि पुरातत्व विज्ञान मूल रूप से व्याख्या पर आधारित होता है और इसमें अनुमान के कई स्तर शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या मामले में भी, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसने जमीन के नीचे एक गैर-इस्लामी ढांचा होने की पहचान की थी। साथ ही साफ तौर पर यह पाया था कि उसे ढांचा गिराए जाने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। उसने यह चेतावनी दी थी कि पुरातत्व रिपोर्टों को कुछ शर्तों के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

इससे मालिकाना हक तय नहीं- सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस मामले में एएसआई की खोजें, अपने आप में मालिकाना हक तय नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक से जुड़े सवालों का फैसला उन तय कानूनी सिद्धांतों और सबूतों के मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए जो दीवानी मुकदमों में पर लागू होते हैं। न कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के आधार पर।

इस बात को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं हैं कि इस जगह पर कभी कोई ऐसा ढांचा मौजूद था, जिसे गिरा दिया गया और उसकी जगह दूसरा ढांचा बना दिया गया। **- सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता**

कानूनी सिद्धांतों की जगह नहीं ले सकते- वहीं, अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर, सबसे बुरे हालात में भी, इस बात को मान लिया जाए, तब भी यह बुनियादी सवाल बना रहेगा कि आज इस संपत्ति के मालिकाना हक पर कौन से कानूनी सिद्धांत लागू होते हैं। उन्होंने दलील दी कि आस्था, ऐतिहासिक दावे और पुरातत्व से जुड़े अनुमान, मालिकाना हक और धार्मिक स्वरूप को तय करने वाले कानूनी सिद्धांतों की जगह नहीं ले सकते।

गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने केंद्र से मांगी मदद

सीएम यादव बोले- वैश्विक परिस्थितियों के कारण गेहूं एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, जूट इम्पोर्ट में भी दिक्कत

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण गेहूं के निर्यात में आई कमी और जूट के आयात में आ रही बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में इस वर्ष डबल हुई पैदावार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से गेहूं उपार्जन का निर्धारित कोटा बढ़ाने की अपील की है, ताकि बंपर उत्पादन का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके।

वैश्विक परिस्थितियों के कारण गेहूं एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा- मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य काफी जटिल है, जिसके कारण भारत से गेहूं का निर्यात लगभग न के बराबर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया के युद्ध जैसे हालातों के चलते विदेशों से आने वाले जूट की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इन विषम

परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने किसानों का साथ नहीं छोड़ा है और वैकल्पिक तौर पर पॉली बैग्स (पीपी बैग) की व्यवस्था कर गेहूं की खरीदी सुचारू रूप से शुरू कर दी है।

किसान संगठनों से चर्चा के बाद बनाई खरीद की रणनीति- मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी को लेकर बताया कि किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर यह तय किया गया है कि उपार्जन केंद्रों पर सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाए। इसके बाद मध्यम श्रेणी के किसानों और फिर बड़े किसानों की फसल खरीदी जाएगी। सरकार ने इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिस पर 40 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर कुल 2625 की दर से भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि जब एमएसपी 2250 थी, तब भी सरकार ने 150 का बोनस दिया था और पिछले साल ?175 बोनस के साथ 2600 में खरीदी की गई थी। उन्होंने विपक्ष और किसानों को आश्वस्त किया कि संकल्प पत्र में किए गए 2700 प्रति क्विंटल के वादे को आगामी तीन वर्षों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाएगा।

पिछले साल का गेहूं भंडारों में भरा

मुख्यमंत्री ने इस बात को भी स्वीकार किया कि प्रदेश के गोदामों में पिछले साल का गेहूं अभी भी बड़ी मात्रा में रखा हुआ है, जो कि भंडारण की दृष्टि से एक चुनौती है। इसके बावजूद सरकार खरीदी काम को प्रभावित नहीं होने देगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भगवान की विशेष कृपा रही है और प्रदेश में गेहूं का उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य (कोटा) मध्य प्रदेश को दिया गया है, वह इस भारी पैदावार के सामने कम पड़ सकता है।इसी कारण राज्य सरकार केंद्र से निरंतर संपर्क में है और उपार्जन का कोटा बढ़ाने का अनुरोध कर रही है ताकि प्रदेश के प्रत्येक पंजीकृत किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

खिवनी अभयारण्य बनेगा वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म का आदर्श मॉडल : मुख्यमंत्री

बाघों की वापसी से 'शांत कॉरिडोर' बना समृद्ध वन्य-जीव आश्रय

युवराज और मीरा ने खिवनी को बनाया टाइगर-लैंड

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राकृतिक रूप से बाघों की बढ़ती मौजूदगी के कारण खिवनी वन्य-प्राणी अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण की सफलता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का विजन खिवनी को एक सुदृढ़ बाघ आवास के साथ-साथ प्रमुख इको-टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे संरक्षण और पर्यटन दोनों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खिवनी आने वाले समय में वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म का आदर्श केंद्र बनेगा।

मालवा-निमाड़ क्षेत्र के शुष्क पर्णपाती वनों में स्थित लगभग 134.7 वर्ग किलोमीटर में फैला खिवनी अभयारण्य, जो पहले केवल रातापानी जैसे बड़े वनों को जोड़ने वाला 'ट्रांजिट कॉरिडोर' माना जाता था, आज बाघों के सुरक्षित प्रजनन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस परिवर्तन को राज्य की सुनियोजित नीतियों और सतत संरक्षण प्रयासों का परिणाम बताया।

खिवनी में बाघ 'युवराज' और 'मीरा' ने इसे अपना स्थायी ठिकाना बनाकर नई पहचान दी है। वन विभाग द्वारा मीरा के तीन शावकों को जन्म देने

की पुष्टि की गई है। ये शावक अब अपनी मां के साथ जंगल में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में खिवनी में लगभग एक दर्जन बाघों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक पुनर्जीवन का स्पष्ट संकेत है।

खिवनी में वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियां, जैसे जंगली कुत्तों (ढोल) की सक्रियता, तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार और भालू की उपस्थिति तथा चौसिंगा जैसे दुर्लभ शाकाहारी जीवों की मौजूदगी ने इसे संतुलित शिकार-शिकारी श्रृंखला और सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र के पुर्नस्थापना का उदाहरण बना दिया है।

खिवनी वन्यजीव संरक्षण की नींव 1982 में रखी गई थी। बाद में खिवनी क्षेत्र का विस्तार कर सीहोर जिले के वन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। अब यह क्षेत्र वन्यजीवों के लिए जीवनरेखा सिद्ध हो रहा है। राज्य सरकार अब ओंकारेश्वर वन्य-प्राणी अभयारण्य के विकास के माध्यम से इस ट्रांजिट कॉरिडोर नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। खिवनी अभयारण्य केवल एक वन क्षेत्र नहीं, बल्कि पुनर्जीवन, संतुलन और नई उम्मीद की प्रेरक कहानी है, जो मध्यप्रदेश को वन्यजीव संरक्षण और इको-पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिला रही है।

भोपाल में कांग्रेस सेवादल का सत्याग्रह

गेहूं खरीदी संकट को लेकर 24 घंटे का उपवास कर रहे कांग्रेस नेता

भोपाल (नप्र)। एमपी में गेहूं खरीदी को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रहीं हैं। प्रदेश में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के गेहूं की खरीद 9 और 15 अप्रैल से शुरू हुई है। लेकिन, गेहूं उपार्जन में पोर्टल की कई समस्याओं के कारण किसान परेशान हो रहे हैं।

किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव सत्याग्रह कर रहे हैं। भार्गव 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान सहित कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। भोपाल के आसपास के जिलों से किसानों को भी इस सत्याग्रह में बुलाया गया है।

सेवादल के संगठक बोले- किसानों को परेशान करना चाहती है सरकार- कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव ने भास्कर से बातचीत में कहा हमारी मुख्य मांग यही है कि गेहूं का उपार्जन मप्र की सरकार को करना चाहिए। मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम दाना-दाना खरीदेंगे। लेकिन, जब खरीदी शुरू होती है तो कहते हैं कि पहले 5 एकड़ के किसानों की खरीदी करेंगे। आप किसानों में भेदभाव क्यों कर रहे हैं।

किसानों में भेदभाव क्यों किया जा रहा- भार्गव ने कहा- जब सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया और किसान ने अपना पंजीयन किया है तो उसका दाना-दाना तुलवाना चाहिए। उसके बावजूद किसानों में भेदभाव किया जा रहा है।

यही नहीं जो किसान पंजीयन के बाद स्लॉट बुक कराने जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आपका सैटेलाइट वेरिफिकेशन नहीं हैं। छोटे किसानों से कहा जा रहा कि आपका खाता डीबीटी के लिए आधार से लिंक नहीं हैं। एक के बाद गेहूं खरीदी में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा गेहूं खरीदी की नहीं बल्कि, किसानों को परेशान करने की है। अवनीश भार्गव ने कहा- एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि आपने किसान को 31 मार्च को ऋण अदा न कर पाने के कारण सहकारी समिति में डिफॉल्टर कर दिया। उससे साल भर का ब्याज ले रहे हैं। जब आपने गेहूं खरीदा ही नहीं तो उसके पहले किसान डिफॉल्टर कैसे हुआ? साल भर का ब्याज लेने का क्या औचित्य है?

नदी में नहाने गए तीन भाई-बहनों की डूबने से मौत

बड़वानी (नप्र)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वरला थाना क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान तीन भाई बहनों की मृत्यु हो गई। उनके शव निकाल लिए गए हैं और आज पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया है।

दरअसल, वरला थाना पुलिस के अनुसार 10 वर्षीय राधा, 8 वर्षीय राजवीर और 6 वर्षीय जयवीर की डूब जाने के चलते मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि देवली के पवन ब्राह्मणे के तीनों बच्चे बुधवार दोपहर अपने मामा के घर बिलवा पनाली आए थे। पवन की बड़ी पुत्री राधिका पहले से यहां पर एक अन्य मामा के घर आयी हुई थी।

नदी में नहाने गए तो डूब गए- दोपहर बच्चों ने खाना खाया और अपनी बड़ी बहन राधिका से मिलने की जिद की और चले गए। इसी बीच रास्ते में अनेर नदी में उनकी नहाने की इच्छा की और वह नहाने लगे। बड़वानी पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह तैरना जानते थे, लेकिन यहां गहराई ज्यादा होने के चलते डूब गए।

नदी के पास दिखे कपड़े और जूते

जब काफी देर तक बच्चे नहीं लौटे तो परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। वे सबसे पहले राधिका के पास गए जो दूसरे मामा के यहां रह रही थी। उन्होंने बताया कि तीनों बच्चे यहां नहीं आए। इसके बाद शाम को नदी के पास उनके कपड़े और जूते चप्पल दिखाई दिए। तीनों के शव बाहर निकाले गए और अस्पताल भेजे गए। घटनाक्रम देख कर मृतक बच्चों के माता-पिता बेहोश हो गए उनका भी उपचार कराया गया। गुरुवार सुबह बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण इस हादसे से स्तब्ध हैं।

सीएम हाउस के पास चौराहों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक

भोपाल (नप्र)। भोपाल में अब शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ये चौराहे शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित हैं और यहां से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आवागमन होता है। इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन या आंदोलन होने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।

बेतवा नदी पुनर्जीवन अभियान 26 अप्रैल से

भोपाल। बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने और नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 'बेतवा अध्ययन एवं जनजागरण समूह' द्वारा जन सहभागिता पर आधारित व्यापक अभियान इस साल अप्रैल, रविवार से ग्राम झिरी (जिला रायसेन-कोलार रोड) में पुनः प्रारंभ हो रहा है।

भोपाल, रायसेन, विदिशा, इदौर, सीहोर आदि स्थानों से अनेक पर्यावरण कार्यकर्ता, नदी-प्रेमी व सामाजिक संस्थाएं इस पवित्र समागम में श्रमदान करेंगे।

बेतवा बचाओ अभियान के निम्न प्रमुख बिंदु हैं- बेतवा नदी में निरन्तर बढ़ते प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 'बेतवा अध्ययन एवं जनजागरण समूह' ने फ़रवरी मार्च 2023 में बेतवा नदी की अध्ययन एवं जनजागरण यात्रा आयोजित की थी द्य सात दिन की उस यात्रा में बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी से कुरवई तक स्थित नदी के किनारे के लगभग दो दर्जन गांवों और आधा दर्जन कस्बों एवं शहरों के स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों, प्रबुद्ध जनों और ग्राम निवासियों से बेतवा की दिन ब दिन बदतर होती स्थिति पर गंभीर चर्चा और जन जागरण किया था। यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री से भी बेतवा नदी के संरक्षण की अपील की गई थी। 2025 में बेतवा नदी का उद्गम स्थल सूख गया था। नदी के सूखे उद्गम स्थल को जन-सहभागिता से पुनर्जीवित करने के लिए पिछले साल 'बेतवा अध्ययन एवं जनजागरण समूह' ने एक सप्ताह के श्रमदान से 55 चैक डैम बनाकर उद्गम स्थल को आंशिक रूप से पुनर्जीवित किया था द्य श्रमदान में भोपाल, विदिशा, गंज बासोदा, सिहोर, बैतूल और इंदौर से सैकड़ों प्रकृति प्रेमी शामिल हुए थे। झिरी गांव के बच्चों ने भी अद्भुत सहभागिता की थीद्य अभियान का नेतृत्व ग्राम सेवा समिति भोपाल के तत्वावधान में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉ आर के पालीवाल और गांधीवादी, डॉक्टर सुरेश गर्ग (विदिशा) कर रहे हैं।

प्रदेश का टूरिस्ट स्पॉट खजुराहो सबसे गर्म

नर्मदापुरम समेत 7 जिलों में लू जैसे हाल पारा 43.8 डिग्री पहुंचा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में गुरुवार को लू जैसे हाल रहे। यहां पारा सामान्य से 4.2 डिग्री तक अधिक रहा। वहीं, नर्मदापुरम् में पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में तापमान 43 डिग्री या इससे पार बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार,नर्मदापुरम्, छतरपुर, रतलाम, सागर, टीकमगढ़, रायसेन, निवाड़ी में पारा सामान्य से ज्यादा रहे। यहां गर्म हवाओं का दौर रहा। भोपाल में भी दिन में गर्मी का अहसास देखने को मिला।

मौसम विभाग के अनुसार, नर्मदापुरम के बाद खजुराहो में पारा 43.4 डिग्री और नौगांव में 43 डिग्री दर्ज किया गया। सीधी में 42.6 डिग्री, दतिया, दमोह, सागर-टीकमगढ़ में 42.2 डिग्री, रायसेन-रतलाम में 42 डिग्री, सतना में 41.8 डिग्री, मंडला में 41.6 डिग्री, गुना-रीवा में 41.5 डिग्री, नरसिंहपुर-खरगोन में 41.4 डिग्री, श्योपुर में 41.2 डिग्री, शाजापुर, खंडवा-दतिया में 41.1 डिग्री, उमरिया में 41 डिग्री रहा।

रीवा के मनगवां में इंदौर के भागीरथपुरा जैसा मटमैला पानी

रंग बिल्कुल काला, बदबूदार भी, बच्चों में पेट दर्द-उल्टी की शिकायत

रीवा (नप्र)। रीवा जिले के मनगवां में पिछले 3-4 दिनों से लोगों के घरों में गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा की तरह यहां भी नलों से पीला, मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसमें कीचड़ जैसे कण भी मौजूद हैं।

दूषित पानी के इस्तेमाल से बच्चों में पेट दर्द और उल्टी की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्वच्छ पेयजल न मिलने के कारण स्थानीय लोग मजबूरी में निजी स्रोतों से पानी खरीद रहे हैं। कई शिकायतों के बाद वर्तमान में नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन में लीकेज की जांच कर रही है।

बदबू से खाना बनाना मुश्किल, बच्चे हो रहे बीमार

मनगवां के कई वार्डों में दूषित जल प्रदाय की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का

कहना है कि जल प्रदाय विभाग को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या जस की तस है। स्थानीय निवासी रामकिशोर पटेल ने बताया हमारे घर में पिछले तीन-चार दिनों से जो पानी आ रहा है, उसे पीना तो दूर, इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हो रही है।रहवासी पूजा तिवारी ने कहा, पानी से इतनी तेज बदबू आ रही है कि खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत की लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

एक अन्य निवासी इरफान खान ने बताया यह समस्या नई नहीं है, हर साल गर्मी में ऐसी दिक्कत होती है, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा खराब है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बीमारियां फैल सकती हैं।

शिकायत के बाद पाइपलाइन की जांच शुरू

जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद अब विभाग ने सुधार कार्य शुरू करने की बात कही है। नगर परिषद मनगवां के एक अधिकारी ने बताया, हमें शिकायतें मिली हैं, टीम को मौके पर भेजा गया है। पाइपलाइन की जांच कराई जा रही है, संभवतः कहीं लीकेज या गंदगी के प्रवेश की समस्या हो सकती है, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा।

वहीं, जल संसाधन विभाग के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गर्मी के कारण जलस्तर कम होने और पुरानी पाइपलाइन के चलते इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन सुधार का काम जारी है।